PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 206 ● भिलाई, शुक्रवार 20 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

चाईबासा में डायन के आरोप में मां-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर जला डाला

चाईबासा । झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में देर रात कथित तौर पर डायन होने के संदेह में एक महिला और उसके मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इस दर्दनाक घटना में मां और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वारदात की जानकारी बुधवार को पुलिस को तब हुई जब 12 आरोपियों ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गांव के करीब 12 लोगों ने मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से गांव में बीमारी और अन्य घटनाओं को लेकर अफवाहें फैली हुई थीं। इसके लिए महिला और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था।

दिल्ली पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ दंपति समेत तीन को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भोपुरा बॉर्डर के पास 1.504 किलोग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद की है। बरामद नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरिफ नामक व्यक्ति बरेली (उत्तर प्रदेश) से भारी मात्रा में हेरोइन लाकर गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता है। सूचना के आधार पर भोपुरा बॉर्डर क्षेत्र में रेकी की गई और संदिग्ध वैगनआर टैक्सी पर नजर रखी गई। तकनीकी और मानवीय खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए इंस्पेक्टर विकास पन्नू के नेतृत्व तथा एसीपी/एएनटीएफ सतेंद्र मोहन के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई। गाजियाबाद की ओर से आती एक संदिग्ध वैगनआर कार को घेराबंदी कर रोका गया।

रायबरेली में तेज रफ्तार कार पलटी, तीन की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा डीह थाना क्षेत्र के परशदेपुर स्थित गोपालपुर गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति से जा रही थी। अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क किनारे पलटते हुए कई बार घूम गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए।

बीजापुर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई

मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर,214 ठिकाने ध्वस्त होने की सूचना

रायपुर/ संवाददाता

बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पांच नक्सलियों के मारे जानें की खबर है। यह कार्रवाई जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल क्षेत्र में नक्सलियों ने पहले सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू की थी। इसके जवाब में जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई भीषण मुठभेड़ में पांच नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए। सुरक्षाबलों को इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त करने की भी जानकारी मिल रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। यह कार्रवाई नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। सुरक्षाबलों को बीजापुर के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ही नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति के तहत जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ में पांच खूंखार नक्सली मारे गए, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों का

नक्सल विरोधी अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले चार दिनों में जवानों ने 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। यह कार्रवाई नक्सलियों की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बरामद विस्फोटक सामग्री से नक्सलियों की बड़ी साजिशों को विफल किया गया है। सुरक्षाबलों की यह लगातार कार्रवाई क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है। खुफिया इनपुट मिले हैं कि देवजी और उसका बेहद करीबी सहयोगी केसा सोढ़ी छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के सघन जंगलों में छिपे हैं। उसके बाद मंगलवार से वहां एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सागर (मल्लाह राजा रेड्डी) के ओडिशा में होने की संभावना है। बाकी तीन इसी सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। बीते 8 फरवरी को रायपुर में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफलड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। शाह ने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क पर कड़े प्रहार ने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया कि सुरक्षा रणनीति और बेहतर आत्मसमर्पण नीति के कारण इस साल 31 मार्च से पहले नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

शाह की समीक्षा के बाद आर-पार की जंग जारी

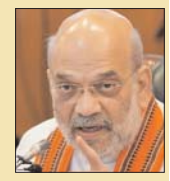

हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर का दौरा कर नक्सल विरोधी अभियानों की गहन समीक्षा की थी। इस बैठक के बाद ही रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए ब्लैक फॉरेस्ट 2.0 जैसे आक्रामक अभियान को हरी झंडी दी गई। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। अगले कुछ महीनों में बस्तर और सीमावर्ती इलाकों से लाल आतंक का नामोनिशान मिटाना। अमित शाह ने इसी हफ्ते दिल्ली में पुलिस स्थापना दिवस समारोह में भी पूरे देश को नक्सल मुक्त करने की बात दोहराई थी। इस सफलता के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2.0 लॉन्च कर दिया है। यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है। इसमें 2000 से अधिक जवान शामिल हैं। सुरक्षाबलों का मुख्य लक्ष्य उन 300 नक्सलियों को घेरना है, जो करेंगुट्टा की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे हैं।

रोबोट डॉग विवाद

राहुल बोले एआई समिट एक अव्यवस्थित तमाशा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में एक यूनिवर्सिटी की तरफ से चीनी रोबोट डॉग प्रदर्शित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे एआई समिट एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बेचा जा रहा है और चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इससे पहले, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स

पर लिखा, एआई को लेकर सरकार ने देश की छवि को पूरी दुनिया में हास्यास्पद बना दिया है। अभी चल रहे एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है।

महिला आरक्षक ने लगाए आरोप

बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके निलंबित यौन शोषण,गर्भपात और ठगी का लगा आरोप.....

बालोद। छत्तीसगढ़ शासन ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बालोद जिले की एक महिला आरक्षक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद की गई है। महिला ने यौन शोषण, तीन बार जबरन गर्भपात और लाखों रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने मुख्य सचिव को साक्ष्यों सहित 12 बिंदुओं वाली विस्तृत शिकायत भेजी थी। राज्य सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। शिकायत के अनुसार, उइके और पीड़िता का परिचय वर्ष 2017 में बालोद के डौंडी में पढ़ाई के दौरान हुआ था। महिला का आरोप है कि उइके ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने, जो स्वयं 2017 में पुलिस आरक्षक बनी थी, उइके की पढ़ाई और कोचिंग के लिए हर महीने चार से पांच हजार रुपये भेजे। वर्ष 2020 में उइके का चयन डिप्टी कलेक्टर

के पद पर हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर उनका व्यवहार बदल गया। महिला ने अपनी शिकायत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोप है कि शादी का आश्वासन देकर आरोपी ने पीड़िता का 2017 से 2025 के बीच तीन बार जबरन गर्भपात कराया। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने बैंक से कर्ज लेकर लगभग तीन लाख तीस हजार रुपये उइके के खाते में हस्तांतरित किए थे। बीजापुर में पदस्थापना के दौरान भी जनवरी से मई 2025 के बीच आरोपी ने महिला का शारीरिक शोषण जारी रखा। पीड़िता ने केवल उइके पर ही नहीं, बल्कि बीजापुर जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी को बचाने के लिए नियमों के विरुद्ध अवकाश दिया गया। साथ ही, फर्जी प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। मुख्य सचिव के निर्देश पर उइके का निलंबन मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर नियत किया गया है। बालोद के डौंडी थाने में मामला दर्ज होने के बाद अब विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

बिना इजाजत विदेशी नहीं जाऊंगा

अनिल अंबानी ने सुप्रीम में टेका माथा; खुद को बताया बेकसूर!

नई दिल्ली/ एजेंसी

देश के दिग्गज कारोबारी और अरबपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहां एक ओर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नया समन भेजते हुए तलब किया है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर ये आश्वासन दिया गया है कि मैं ईडी की जांच में पूरा सहयोग करूंगा और बिना इजाजत देश नहीं छोड़ूंगा। गौरतलब है कि अनिल अंबानी पर

ईडी की जांच उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा कथित 40000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चल रही है। बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों की जांच के संबंध में स्ट्ष्ट में एक पीआईएल में एफिडेविट फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में अनिल अंबानी ने कहा कि संबंधित कंपनियों में उनका रोल सिर्फ एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का था और वह उन कंपनियों के रोजाना के मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मामलों में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। एफिडेविट में उन्होंने आगे कहा है कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। अंबानी ने बताया कि जुलाई 2025 में जब इस मामले की ईडी जांच शुरू हुई थी, तब से अब तक उन्होंने भारत नहीं छोड़ा है और फिलहाल भी भारत से बाहर जाने का कोई प्लान या इरादा नहीं है।

राजस्थान में बारिश, घने बादलों ने आसमान को घेरा, बूंदाबांदी से हुई एनसीआर के सुबह की शुरुआत

जयपुर। जयपुर समेत राजस्थान में कई जगह बुधवार सुबह हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बारिश व बूंदाबांदी का दौर रात से ही शुरू हो गया था। उधर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह मौसम ने करवट ली और घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश की फुहारें देखने को मिलीं। बदलते मौसम और तेज हवा के कारण वायु गुणवत्ता में भी आंशिक सुधार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 18 फरवरी को दिनभर सामान्यत: बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।

फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दी नसीहत

राज्य घाटे में चल रहे है फिर भी मुफ्त की स्कीमें चल रहीं-सुप्रीम

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज (मुफ्त सुविधाओं) पर सख्त टिप्पणी की है और इसे देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य वित्तीय घाटे में चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुफ्त सेवाओं का वितरण जारी है। सीजेआई ने यह भी कहा कि ऐसे फिजूलखर्ची से देश के आर्थिक विकास को गंभीर नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम केंद्र सरकार मामले की

सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि राज्य सरकारें मुफ्त भोजन, साइकिल, बिजली, और अब नकद राशि को सीधे लोगों के खातों में स्थानांतरित कर रही हैं। यह फिजूलखर्ची केवल विकास कार्यों के लिए जरूरी धन को खा रही है। सीजेआई ने कहा कि कल्पना कीजिए, अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी यही नीतियां लागू की जा रही हैं। अगर आप सुबह से ही मुफ्त सुविधाएं देने की शुरुआत कर देते हैं, तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? राज्य को यह हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि इस खर्च को कहां से पूरा किया जाएगा। सीजेआई ने यह सवाल उठाया कि अगर राज्य घाटे में चल रहे हैं, तो मुफ्त सुविधाएं देने के लिए धन कहां से आएगा? उन्होंने उदाहरण दिया कि राज्य एक साल में जो राजस्व इकट्ठा करते हैं।

एआई इम्पैक्ट समिट

मोदी बोले-नई तकनीक पर युवा पीढ़ी का भरोसा अभूतपूर्व है

नयी दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक सभी की पहुंच सुनिश्चित किए जाने और समावेशन एवं सशक्तीकरण के उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल करने की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मनुष्य महज 'डेटा' बिदु या कच्चा माल बनकर न रह जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना ??है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया की भलाई के लिए वास्तव में तभी काम आएगी जब इसे साझा किया जाएगा और इसके कोड सार्वजनिक होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश एआई से डरता नहीं है बल्कि इसमें भविष्य की संभावनाएं देखता है। मोदी ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमें एआई को खुला आकाश देना है, लेकिन साथ ही लगाम अपने हाथ में रखनी है। इस सम्मेलन में अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और दुनियाभर के कई नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई हमारे तंत्रों को अधिक स्मार्ट, अधिक दक्ष और अधिक प्रभावी बनाएगा। यह लोगों के लिए रचनात्मक भूमिकाएं अपनाने के और अवसर खोलेगा। यह नवोन्मेष, उद्यमिता और नये उद्योगों के सृजन का बड़ा अवसर है। मोदी ने कहा, कुछ देशों का मानना है कि एआई को गोपनीय और बंद तरीके से विकसित किया जाना चाहिए लेकिन भारत अलग है। हमारा मानना ??है कि एआई सही मायने में दुनिया के हित में तभी काम करेगा जब इसे साझा

किया जाएगा और इसके कोड सार्वजनिक होंगे। तभी लाखों युवा दिमाग इसे और बेहतर बना पाएंगे।प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं- एक वे जो एआई में डर देखते हैं और दूसरे वे जो एआई में समृद्धि देखते हैं। उन्होंने कहा, मैं गर्व और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमें इसमें डर नहीं दिखता। भारत एआई में समृद्धि देखता है, भारत एआई में भविष्य देखता है। भारत एआई में अवसर और आने वाले कल की रूपरेखा देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी भारत में हो रही है, जो मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभा के सबसे बड़े भंडार का केंद्र है। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव इतिहास में एक परिवर्तनकारी अध्याय है। भारत एआई क्रांति का केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि वह इसका नेतृत्व कर रहा है और इसे आकार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी बनाता है बल्कि उसे अभूतपूर्व गति से अपनाता भी है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को नयी प्रौद्योगिकी को लेकर संदेह है लेकिन युवा पीढ़ी एआई को जिस तरह अपना रही है, वह अभूतपूर्व है। एआई शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी को लेकर भी यहां जबरदस्त उत्साह रहा है।

मुकेश अंबानी का बड़ा एलान, कहा- अगले सात साल में 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे

नई दिल्ली: एआई इंपैक्ट समिट में भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा दौर आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा, एआई कई क्षेत्रों में नए दौर की शुरुआत कर सकता है। उन्होंने कहा, दुनिया इस बात पर बहस कर रही है कि क्या एआई के कारण ताकत कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी। या एआई सभी के लिए मौके और सबके लिए आसान अवसर का माध्यम बनेगा। उन्होंने मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमता के असर को रेखांकित करते हुए कहा, आज एआई को लेकर दुनिया दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता कम, महंगे एआई और कंट्रोल्ड डाटा की तरफले जाता है।

छुरा-राजिम मार्ग के कायाकल्प को मिली बड़ी मंजूरी 145 करोड़ की लागत से होगा चौड़ीकरण और उन्नयन

विधायक रोहित साहू के प्रयासों से संवरेगी राजिम विधानसभा की मध्यरेखा

राजिम। गरियाबंद जिले के प्रमुख मार्गों में से एक छुरा से राजिम तक के सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में विधायक रोहित साहू का प्रयास सफल हुआ है। राजिम विधानसभा को हर हफ्ते नई-नई सौगातें देने वाले विधायक रोहित साहू के सतत् प्रयासों और विकासपरक विजन के चलते बहुप्रतीक्षित राजिम से छुरा व्हाया कौन्दकेरा तरीघाट मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति छग शासन लोक निर्माण विभाग ने प्रदान की है और इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छुरा-राजिम मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन के लिए 145 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति के साथ ही क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने वाली है, जिससे क्षेत्र की दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन सुगम होगा और उनके समय व संसाधन की बचत होगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू के अथक प्रयासों और दृढ़ इच्छाशक्ति को दिया है। छुरा से राजिम मार्ग बनने से अनेक गांव बेलटुकरी, भैंसातरा, कौन्दकेरा, सेमराडीह, तरीघाट, कुंडेल, छुईहा, जमाही, जुनवानी, पक्तियाँ, मंड़ेली, लोहझर जैसे अनेक ग्राम चौड़ी सड़क से जुड़ेंगे। इसके साथ ही जतमई घटारानी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी सुगम होगी। यह मार्ग प्रसिद्ध राजिम कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात का मुख्य केंद्र होता है। वर्तमान में इस मार्ग की स्थिति जर्जर होने और संकरा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। क्षेत्रीय जनता वर्षों से इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रही थी। क्षेत्र की इस ज्वलंत समस्या को भांपते हुए विधायक रोहित साहू ने भाजपा सरकार बनने के बाद से ही इस मार्ग के उन्नयन को अपनी प्राथमिकताओं में रखा था। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष लगातार इस मुद्दे को मजबूती से उठाया।

राजिम विधानसभा की मध्यरेखा बनने से खुलेंगे विकास का नया द्वार : रोहित साहू-विधायक रोहित साहू ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छुरा-राजिम मार्ग का चौड़ीकरण क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। दुर्घटनाओं को रोकने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए यह परियोजना अत्यंत आवश्यक थी। 145 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति मिलने से अब जल्द ही काम शुरू होगा। हमारा उद्देश्य क्षेत्र को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। सड़क के चौड़ीकरण,मजबूतीकरण से बेहतर कनेक्टिविटी, कम समय में यात्रा, व्यापार में वृद्धि, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस मार्ग के बनने से छुरा, और राजिम के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यात्रियों का समय बचेगा। साथ ही राजिम , घटारानी,जतमई आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह एक बड़ी सौगात होगी। विधायक रोहित साहू ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार प्रकट किया। विधायक रोहित साहू ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि युद्धस्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। राजिम विधानसभा का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जो विकास से अछूता हो। राजिम विधानसभा की यह मध्यरेखा हमारे क्षेत्र की जीवनरेखा बनेगी और इससे आवागमन की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा।विधायक रोहित साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण विकास कार्यों को द्रुत गति मिल रही है। यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि जनता की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ रूपये के विकास कार्यो को स्वीकृति मिली

जांजगीर-चांपा। विधायक ब्यास कश्यप के प्रयास से विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ रूपये के विकास कार्यो को स्वीकृति मिली है। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विधायक ब्यास कश्यप ने बताया कि जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 08 ग्राम पंचायतों में कुल 02 करोड़ रूपये की लागत से विविध निर्माण कार्यो को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्री में धरमू साहू के घर से चंद्रशेखर यादव के घर की तरफ पक्की नाली निर्माण के लिए 5 लाख रू., शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला दर्री में अहाता निर्माण के लिए 16.68 लाख रू., ग्राम दर्री के आंगनबाड़ी भवन केन्द्र क्र. 02 में भवन मरम्मत के लिए 3.00 लाख रू. एवं शौचालय निर्माण के लिए 0.50 लाख रू. ग्राम पंचायत जगमहंत के दर्रीपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10.00 लाख रू., आरतहरण के घर से दर्री तालाब की ओर नाली निर्माण के लिए 8.18 लाख रू., आंगनबाड़ी भवन मरम्मत के लिए 3.00 लाख रू, एवं आंगनबाड़ी भवन केन्द्र क्र. 1 में शौचालय निर्माण के लिए 1.00 लाख रू., ग्राम पंचायत भैसदा में मुक्तिधाम शेड एवं प्रतिक्षालय निर्माण के लिए 7.00 लाख रू. खोलबहरा सूर्यवंशी के घर से कोलिहाभाठा की ओर नाली निर्माण के लिए 8.68 लाख रू. आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 02 में भवन मरम्मत के लिए 2.00 लाख रू. एवं शौचालय निर्माण के लिए 0.50 लाख रू., ग्राम पंचायत पुटपुरा में मोनू के घर से नहर की ओर नाली निर्माण के लिए 3.00 लाख रू., सबरिया डेरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 7.00 लाख रू., सबरिया डेरा में नाली निर्माण के लिए 4.00 लाख रू. छतदार चबूतरा निर्माण के लिए 3.68 लाख रू., आंगनबाड़ी केन्द्र क्र 04 में भवन निर्माण के लिए 7.00 लाख रू., आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 03 में शौचालय निर्माण के लिए 0.50लाख रू., ग्राम पंचायत तेंदुवा में आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 02 में भवन निर्माण के लिए 7.00 लाख रू., भाठापारा में अनंदराम सतनामी के घर से नहर फाल की तरफ नाली निर्माण के लिए 6.18 लाख रू. जूना तालाब में पिचिंग कार्य के लिए 12.00 लाख रू, ग्राम पंचायत पाली में सूर्यवंशी मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 7.00 लाख रू, जगत सायकल स्टोर से गणेश सूर्यवंशी के घर की ओर नाली निर्माण के लिए 4.18 लाख रू, मुस्लिम कब्रिस्तान मे अहाता निर्माण के लिए 7.00 लाख रू, आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 02 व 03 भवन मरम्मत कार्य के लिए 6.00 लाख रू. आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 03 व04 में शौचालय निर्माण के लिए 1.00 लाख रू, ग्राम पंचायत ठाकुरदिया में खिरू साण्डे के घर से मेनरोड की ओर नाली निर्माण के लिए 8.00 लाख रू।

जन आरोग्य समिति व पंचायत प्रतिनिधियों का दो दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण सम्पन्न

महासमुंद। ग्राम पंचायत अचानकपुर में जन आरोग्य समिति के सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुँचाना है।प्रशिक्षण के पहले दिन ग्राम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जुड़ी जन आरोग्य समिति के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा, प्रचार-प्रसार एवं शासन द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, रोकथाम एवं समय पर उपचार के महत्व पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत को स्वस्थ पंचायत के रूप में विकसित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य एवं समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।कार्यक्रम की व्यवस्था में ग्राम पंचायत अचानकपुर के सरपंच श्री ऋषि चौधरी एवं सचिव श्री रामकुमार नायक का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण में पीएचसी सिरपुर प्रभारी वीरेंद्र कुमार नायक सहित सीएचसी रायतुम, जलकी, अचानकपुर क्षेत्र की जन आरोग्य समिति द्वारा सक्रिय सहभागिता निभाई गई। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में जलकी सरपंच श्रीमती सरिता दीवान, छपोराडीह सरपंच श्रीमती सोनिया रमन, बंदोरा सरपंच श्री हीरालाल निषाद, उपसरपंच श्री भानु प्रताप पटेल, उपसरपंच जलकी श्री गोल्डी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया। प्रशिक्षण में जिला समन्वयक जागृति बरेठा, प्रशिक्षक देवकी साहू, चारू दीवान एवं एसपीएस हेमवती द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों को सक्रिय रूप से संचालित करने का संकल्प लिया।

पाली महोत्सव में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर आधारित स्टॉल रही आकर्षण का केंद्र

कोरबा। पाली महोत्सव 2026 के अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी बसंत मिंज के मार्गदर्शन में एकीकृत बाल विकास परियोजना पाली द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक विभागीय स्टॉल स्थापित किया गया। स्टॉल का मुख्य थीम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर केंद्रित था, जिसे मॉडल के रूप में सुसज्जित कर प्रदर्शित किया गया। स्टॉल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता, पंजीयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं लाभ प्राप्ति की संपूर्ण जानकारी सरल एवं दृश्यात्मक माध्यम से प्रस्तुत की गई। आगंतुकों ने मॉडल के माध्यम से योजना की प्रक्रियाओं को समझा तथा उपस्थित पर्यवेक्षको से विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। स्टॉल में वजन त्यौहार पर केंद्रित विशेष कॉर्नर भी बनाया गया, जिसमें बच्चों के नियमित वजन मापन, कुपोषण की पहचान, ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं पोषण परामर्श की जानकारी दी गई। आम नागरिकों, विशेषकर माताओं एवं अभिभावकों ने इसमें विशेष रुचि दिखाई।इसके अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे रेडी टू ईट यूनिट का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमजनों को सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए हितग्राहियों को लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। पाली महोत्सव के दौरान विभागीय स्टॉल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्टॉल में प्रदर्शित मॉडलों एवं योजनाओं की प्रस्तुति की सराहना करते हुए विभागीय टीम को जनजागरूकता के इस सराहनीय प्रयास हेतु बधाई दी। साथ ही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने हेतु आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए। पाली महोत्सव में लगाए गए इस विभागीय स्टॉल ने न केवल जनजागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बना। बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने स्टॉल का अवलोकन किया तथा विभागीय पहल की सराहना की।

नशा मुक्ति एवं सायबर जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

जांजगीर-चांपा । थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम उदयभांठा एवं थाना बिर्रा क्षेत्र के ग्राम धीवरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशा मुक्ति/सायबर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोगों के बारे में लोगो को जागरूक किया गया। नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित कर अवैध शराब के विरुद्ध सशक्त संदेश दिया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी, सायबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, अंजान लिंक पर क्लिक न करे, ओटीपी शेयर न करे के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (ढ्ढक्र) के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा निरीक्षक कमलेश सेंडे थाना प्रभारी नवागढ़ के नेतृत्व में नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम उदयभांठा एवं थाना प्रभारी बिर्रा निरीक्षक जय कुमार साहू द्वारा ग्राम धीवरा में नशा मुक्ति एवं सायबर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए अवैध शराब के खिलाफ एवं सायबर अपराध से बचने के संबंध में जागरूक किया गया। जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले में अवैध शराब, नशा कारोबार एवं सामाजिक अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा।

जनगणना 2027 : जिले में तैयारी शुरू, प्रथम चरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी

कोरबा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में आयोजित किया जाएगा, जिसका समय प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण दो अलग-अलग सत्रों में क्षेत्रवार संपन्न होगा। प्रथम सत्र के अंतर्गत दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2026 को जिले के समस्त ग्रामीण चार्ज के अधिकारियों, जिनमें कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोड़ीउपरोड़ा, भैसमा, बरपाली, दीपका, हरदीबाजार, दर्री, अजगरबहार एवं पसान के सभी तहसीलदार शामिल हैं, को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में, द्वितीय सत्र का आयोजन दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इसमें समस्त नगरीय क्षेत्र के अधिकारियों, जिनमें नगर पालिक निगम कोरबा के सभी जोन कमिश्नर, नगर पालिका परिषद कटघोरा, दीपका, बाकीमोंगरा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा नगर पंचायत छुरीकला एवं पाली के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी ने समस्त संबंधित चार्ज अधिकारियों और अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनगणना लिपिक के साथ नियत तिथि और समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जनगणना की तकनीकी बारीकियों और गणना प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों की जानकारी दी जाएगी ताकि जिले में जनगणना का कार्य त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके।

नक्सल बैठकों से वैदिक मंत्रों तकः केरलापेंदा राम मंदिर बना नवजागरण का दीप

सुकमा।-धुर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत केरलापेंदा का राम मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था की पुनर्स्थापना और बदलते दौर का जीवंत प्रतीक बन चुका है। जिस परिसर में कभी नक्सली बैठकें होती थीं और जहाँ भय का साया पसरा रहता था, आज वहीं वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि, घी की आहुतियों की सुगंध और ÷जय श्रीराम÷ के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा है।ग्रामीणों की आँखों में वह समय आज भी ताजा है जब वर्ष 1978 में सीमित संसाधनों के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कठिन परिस्थितियों में दूर प्रदेश से भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएँ यहाँ स्थापित की गई थीं। वह केवल निर्माण नहीं, बल्कि अटूट आस्था का प्रमाण था।लेकिन समय का पहिया ऐसा भी घूमा कि लगभग 21 वर्षों तक मंदिर के पट बंद रहे। नक्सली प्रतिबंधों के कारण पूजा-अर्चना ठप हो गई। जिन चौखटों पर दीप जलते थे, वहाँ सन्नाटा छा गया। आस्था परद्ध लगे इस विराम ने गाँव की आत्मा को कहीं न कहीं घायल कर दिया था।21 वर्षों के बाद सीआरपीएफ के सहयोग से खुले मंदिर के पटपिछले वर्ष सीआरपीएफ के सहयोग से मंदिर के द्वार पुनः खोले गए। यह केवल एक ताला खुलना नहीं था, बल्कि वर्षों से बंद पड़ी उम्मीदों का द्वार खुलना था। इसके बाद नियमित पूजा-पाठ प्रारंभ हुआ और अब 21 वर्षों बाद आयोजित एक कुंडीय यज्ञ ने पूरे क्षेत्र को भाव-विभोर कर दिया।हवन कुंड से उठती अग्नि की लपटें मानो यह संदेश दे रही थीं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे चीर सकता है। सैकड़ों श्रद्धालु-बुजुर्ग, युवा, महिलाएँ और बच्चे-आँखों में श्रद्धा और हृदय में विश्वास लेकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कई बुजुर्गों की आँखें नम थीं; वे कह रहे थे, ÷आज हमारे जीवन का अधूरा सपना पूरा हुआ है।÷भावुक हुई दीपिका शोरीइस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने भावुक शब्दों में कहा,÷जहाँ कभी भय और असुरक्षा का वातावरण था, वहाँ आज श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश फैल रहा है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का पावन संकेत है।

नगर पंचायत फिंगेश्वर में 389.04 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास सम्पन्न

विधायक रोहित साहू बोले—राजिम विधानसभा में हर सप्ताह मिल रही करोड़ों की सौगात

फिंगेश्वर। नगर पंचायत फिंगेश्वर में अधोसंरचना मद अंतर्गत 389.04 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं भूमिपूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजिम विधायक रोहित साहू रहे, जबकि नगर पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष धनराज सूर्यवंशी ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों में इन्द्राणी नेहरू साहू, चंद्रशेखर साहू, मंजुलता हरित, राजू साहू, संतोष ढीढी, संतोष मांडले, दीपक श्रीवास, जगदीश यादव, अनिल चंद्राकर, चंचल कमलेश यदु, कुसुम डोमार ध्रुव, रामाधीन साहू, हेमनारायण महिलांग, पद्मा यदु, शांति कोसरे, रामनारायण टांडेकर, नरेन्द्र रात्रे, अभिषेक सोनी, चांदनी कमलेश कश्यप, हरीश हरित एवं टीकाचंद ध्रुव शामिल रहे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पूर्व अतिथियों द्वारा अस्पताल के पीछे निर्मित स्टॉफ क्वार्टर तथा मितानिन प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पटाखों, गाजे-बाजे और राउत नाचा के साथ अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर तिलक-माल्यार्पण कर किया गया, तत्पश्चात विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण शिलाओं की विधिवत पूजा-अर्चना की गई।कार्यक्रम का संचालन खुमान सिंह ध्रुव ने किया, जबकि स्वागत भाषण फणीकेश्वर नाथ महाविद्यालय के अध्यक्ष राजू साहू ने दिया। महाविद्यालय के छात्रङ्कछात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उपस्थित जनों ने सराहना की। नगर पंचायत अध्यक्ष धनराज सूर्यवंशी ने अपने उद्बोधन में विधायक रोहित साहू का आभार जताते हुए कहा कि फिंगेश्वर नगर को करोड़ों की सौगात मिली है। उन्होंने सर्व समाज मांगलिक भवन हेतु 1 करोड़ रुपये तथा विभिन्न वार्डों में सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भी रखी। मुख्य अतिथि राजिम विधायक रोहित साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथङ्कसबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राजिम विधानसभा क्षेत्र में सड़क, भवन, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में राजिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है। हर सप्ताह राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति मिल रही है। अभी हाल ही में राजिम से छुरा व्हाया कौन्दकेराङ्कतरीघाट सड़क चौड़ीकरण के लिए 145 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह सभी योजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं। आज हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ रहा है, नगरों में अधोसंरचना मजबूत हो रही है और आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राजिम विधानसभा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। बीते कुछ महीनों में सैकड़ों करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। विधायक ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीब, किसान, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण है। आवास, राशन, स्वास्थ्य सुविधा और सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में फिंगेश्वर नगर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में और भी बड़े विकास कार्य प्रारंभ होंगे तथा जन-जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।उन्होंने आगे कहा कि फिंगेश्वर नगर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नगर अध्यक्ष की मांग पर उन्होंने सर्व समाज मांगलिक भवन, मितानिन भवन में बाउंड्रीवाल ,महाविद्यालय के छात्रों की मांग पर उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम में कपड़ो हेतु 50000/- रूपये सहित अन्य आवश्यक कार्यों की घोषणा भी की। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में सड़क, भवन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए हर वार्ड तक विकास पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में डॉ. परितोष कुदेशिया, उत्तम राजवंशी, सियाराम ध्रुव, नूतन साहू, दूजलाल बंजारे, नोसराम साहू, जीतेंद्र श्रीवास, पिंटू श्रीवास, खिलावन सोनवानी, गोपचंद बैनर्जी, संतोषी श्रीवास्तव, सीमा ठाकुर सहित नगर पंचायत के अधिकारीङ्ककर्मचारी, मितानिन बहनें, स्वास्थ्य विभाग का अमला एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

आपसी विवाद में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, तनाव का माहौल

रायपुर। दुर्ग शहर के शांति नगर क्षेत्र में एक बार फिर हिंसक वारदात सामने आई है। सोमवार रात करीब 8:30 बजे आपसी विवाद के चलते एक नाबालिग युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक क्षय कुमार उर्फ नानू मोहन नगर थाना क्षेत्र के शक्ति नगर में निकाली जा रही भोले बाबा की बारात देखने गया था। इसी दौरान बारात में शामिल कुछ युवकों के साथ उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो जल्द ही हिंसक रूप ले बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर युवकों ने पहले नानू के साथ मारपीट की और फिर चाकुओं से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर नशे की हालत में थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, इलाके में अवैध नशे और आपराधिक गतिविधियों को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शांति नगर और शक्ति नगर एक-दूसरे से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां पूर्व में भी विवाद की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

राजधानी में दिनदहाड़े 38 लाख की उठाईगिरी

रायपुर। राजधानी में 48 लाख की उठाईगिरी का सनसनीखेज मामला समाने आया है। पुलिस के सक्रियता के चलते आरोपी को धरदबोचा गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एफसीआई कर्मचारी ज्ञान प्रकाश पांडेय अपने बहन के भूमि सौदे के मामले को लेकर भूमि पंजीयन एवं स्टॉप कार्यालय आए थे तथा अपने एक मित्र को 38 लाख रूपए लेकर आने को कहा इस बीच कार में बैठे नितिन को लालच आ गया तथा उसने अपने एक दोष के सहयोग से यह रकम पार कर दी। एफसीआई कर्मचारी ने इसकी रिपोर्ट सिविल लाईन थाने में दर्ज कराई क्राईम कंट्रोल के प्रभारी वहां पर पहुंचे तथा संदिग्त नितिन से पूछताछ की। पहले वे घूमाता रहा लेकिन सीसीटीवी कैमरा के फूटेज के आधार पर एक लड़का बैक लेकर ऑफिस के पीछे जाते हुए देखा गया। नितिन ने पुलिस के सामने स्वीकार किया उसने लालच में आकर यह कृत्य किया है। पुलिस ने नितिन को पूछताछ के लिए पकड़ लिया है, वे पहले भी कई मामले में आरोपी था।

40 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ महिला विक्रेता गिरफ्तार

रायपुर। जिले की कोनी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाली एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना कोनी पुलिस को दिनांक 17/02/26 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि प्रभा देवी वर्मा निवासी ग्राम जलसों अपने घर के आंगन में अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखी हैं बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश कर रही हैं।

देशसेवा का संकल्प और सफलता की उड़ान : मुंगेली की सुप्रिया सिंह बनी लेफ्टिनेंट

सुप्रिया से प्रेरणा लेकर युवाओं को लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

- मुख्यमंत्री श्री साय ने किया सम्मानित, राज्य का नाम रोशन करने पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं
- उनकी माता श्रीमती संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता श्री वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथा रैंक प्राप्त करने वाली मुंगेली की सुश्री सुप्रिया को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रिया और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुँह मीठा कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हों, तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया का अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सुप्रिया से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम टेढ़ाधौंरा की 23 वर्षीय सुप्रिया ठाकुर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथी रैंक प्राप्त कर मुंगेली जिला सहित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशसेवा के अटूट संकल्प के बल पर वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें मुख्यमंत्री

ने शुभकामनाएं दी है। ग्राम टेढ़ाधौंरा निवासी सुप्रिया सिंह श्रीनेत एक किसान परिवार से आती हैं। उनकी माता श्रीमती संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता श्री वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया। परिवार के स्नेहिल और अनुशासित वातावरण में पली-बढ़ी सुप्रिया ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने कक्षा 10वीं में 71 प्रतिशत और 12वीं में 58 प्रतिशत अंक अर्जित किए। इसके बाद उन्होंने बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग अध्ययन के दौरान ही उन्होंने एनसीसी को अपनाया और अपने नेतृत्व कौशल के बल पर जूनियर अंडर ऑफिसर के पद तक पहुंचीं। एनसीसी के प्रशिक्षण ने उनके भीतर अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ किया। यहीं से भारतीय सेना में अधिकारी बनने का उनका संकल्प आकार लेने लगा। वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग पूर्ण करने के बाद सुप्रिया ने पूरी एकाग्रता के साथ सीडीएस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की। कठोर परिश्रम, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमिशन के अंतर्गत आयोजित एसएसबी साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की। उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली प्रेरक कहानी है। शैक्षणिक और सैन्य उपलब्धियों के साथ-साथ सुप्रिया सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं। नृत्य उनकी प्रमुख रुचि है, जो उनके व्यक्तित्व को ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सुप्रिया सिंह श्रीनेत की यह सफलता न केवल मुंगेली, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

रायपुर में गांजा बेचते एक व्यक्ति पकड़ाया

रायपुर। राजधानी की एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट की टीम ने एक व्यक्ति को थाना गंज क्षेत्रांतर्गत एक्सप्रेस-वे के पास गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 6.110 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत एक्सप्रेस-वे स्थित एक पान दुकान पास एक व्यक्ति गांजा रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एण्ड साइबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रभारियों को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति को चिन्हांकित करते हुये घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रविन्द्र कुमार सतपथी निवासी काटाभांजी उडीसा होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग में अलग - अलग पैकेट में गांजा रखा होना पाया गया। आरोपी रविन्द्र कुमार सतपथी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 6.110 किलोग्राम गांजा एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

भाजपा की संयुक्त बैठक में संगठन विस्तार पर जोर-किरण सिंह देव....

- योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठक राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पार्टी के सभी सात मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी एक सक्रिय और निरंतर कार्य करने वाला संगठन है। उन्होंने बताया कि हाल ही में गठित सभी मोर्चों की यह पहली संयुक्त बैठक थी, जिसमें जिला, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं की जानकारी केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए 'चौपाल' जैसे माध्यमों से सीधे संवाद स्थापित करने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही बजट, विकास और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी विचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि पार्टी के सभी मोर्चे एक सेतु की तरह कार्य करते हुए संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।

नल से जल ने बदली गांव की तस्वीर, दीपा की जिन्दगी में आई खुशहाली

- घर में आया जल-जीवन, चौघड़ा गांव में जल क्रांति की कहानी

रायपुर/ संवाददाता

जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करना है, ताकि सभी घरों, स्कूलों और आंगनवाडी केन्द्रों तक नल से पानी पहुंच सके।इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जीवन में बदलाव की एक प्रेरक और सशक्त कहानी ग्राम पंचायत चौघड़ा के लोहारपारा से सामने आई है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ की निवासी दीपा के लिए स्वच्छ पेयजल कभी एक सपना हुआ करता था, जिसे पूरा करने के लिए रोज़ाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। घर से दूर स्थित कुएँ से पानी लाने में उनका काफी समय और मेहनत खर्च हो जाता था, जिससे दैनिक जीवन के अन्य कार्य प्रभावित होते थे। हर घर नल से जल योजना के लागू होने के बाद दीपा और उनके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब उनके घर पर ही शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। पानी के लिए भटकने की मजबूरी खत्म हो गई है और समय की बचत होने से दीपा अब परिवार, बच्चों और अन्य घरेलू कार्यों पर बेहतर ध्यान दे पा रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां स्वच्छ पानी के कारण परिवार की सेहत में स्पष्ट सुधार हुआ है। दीपा बताती हैं कि नल से जल मिलने के बाद जीवन में सुविधा, सम्मान और सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। उन्होंने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना केवल पानी नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की गारंटी लेकर आई है। उनके शब्दों में यह पहल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदल रही है। जल जीवन मिशन की यह पहल आज ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। चौघड़ा गांव की दीपा की कहानी यह साबित करती है कि जब योजनाएं ज़मीन पर उतरती हैं, तो वे सिर्फ नल से पानी नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली और आत्मसम्मान भी पहुंचाती हैं।

भाजपा सरकार को घेरने विपक्ष बना रहा रणनीति-विधायक पुरंदर मिश्रा

- भाजपा कांग्रेस विधायक दल की बैठक 23 फरवरी को

रायपुर/ संवाददाता

विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक इसी दिन बुलाई जाएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। भाजपा के विधायकों द्वारा भी अनेक प्रश्न लगाए गए हैं, उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अलावा रायपुर में विकास कार्यों को लेकर कई पश्न लगाए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 23 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किए जाने की सूचना है। भाजपा विधायक कांग्रेस के जवाबों का उत्तर देंगे। वहीं ट्रेजरी बैंच से भी उत्तर दिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इनके लिए अलग-अलग तैयारी कर ली है। अलग-अलग दिन मंत्रियों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए एक चार्ट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे अब ध्यानाकर्षण भी लगाया जा रहा है। राज्य में विभिन्न उत्तरों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा कांग्रेस विधायक दल की बैठक शीघ्र बुलाए जाने के संकेत हैं, यह बैठक 22 फरवरी को बुलाए जाने की चर्चा है। इसमें सरकार को खजिन, शराब माफिया तथा गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेगा। बजट की तैयारियों को देखते सभी विभागों द्वारा इस समय तैयारी की जा रही है, प्रश्नों का उत्तर बनाया जा रहा है, धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। एग्रीटेक पोर्टल, धान खरीदी में विलंब आदि मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा।

गौ तस्करी मामले में फरार आरोपी जागेश्वर पकड़ाया

रायपुर। जशपुर पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपी जागेश्वर को मनोरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गौ तस्करी के मामले में जनवरी माह से फरार था। बता दें कि दिनांक 18.01.26 की रात्रि करीबन 8 बजे थाना आस्ता पुलिस को ग्राम खोंगा के ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि ग्राम खोंगा के ग्रामीण रास्ते से दो संदिग्ध व्यक्ति, कुछ गौ वंशों को बेरहमी पूर्वक मारते पीटते हुए, पैदल हांक कर जल्दी जल्दी, झारखंड राज्य की ओर ले जा रहे हैं, जिस पर थाना आस्ता पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, तत्काल ग्राम खोंगा रवाना हुआ गया,जहां पुलिस ने पाया कि ग्रामीणों के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को 4 नग गौ वंशों सहित पकड़ कर रखा गया है, पूछताछ पर पकड़े गए संदिग्ध आरोपी ने अपना नाम बनर्जी भगत उम्र 55 वर्ष , निवासी ग्राम डड़गांव, चौकी मनोरा, जिला जशपुर छग का रहने वाला बताया था और बताया था कि वह अपने साथी के साथ उक्त गौ वंशों को झारखंड ले जा रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर उसके फरार साथी जागेश्वर लकड़ा उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुर झारखंड को भी चिन्हित कर लिया था। जिसकी पता साजी की जा रही थी। पुलिस के द्वारा मौके से 4 नग गौ वंशों को सकुशल बरामद कर लिया गया है व पशु चिकित्सक से गौ वंशों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस फरार आरोपी जागेश्वर लकड़ा उम्र 58 की लगातार पता साजी कर रही थी।

मंत्री लखन लाल देवांगन के आतिथ्य में श्रमिक सम्मेलन का हुआ आयोजन

श्रमिकों का सशक्तिकरण ही समृद्ध और विकसित छग की आधारशिला

- श्रमिकों के खून-पसीने की मेहनत से ही प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा
- सम्मेलन में 3110 श्रमिकों को कुल 1.23 करोड़ की सहायता राशि की गई वितरित

रायपुर/ संवाददाता

श्रमिकों के सम्मान और उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से कोरबा शहर के टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में श्रमिक सम्मेलन का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन में श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि भी वितरित की गई। इस अवसर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, सभापति नगर निगम श्री नूतन ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रमवीर उपस्थित थे। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमवीर प्रदेश की रीढ़ हैं। उनके अथक परिश्रम और समर्पण से ही बड़े निर्माण कार्य, अधोसंरचना विकास एवं औद्योगिक प्रगति संभव हो पा रही है। श्रमिकों के खून-पसीने की मेहनत से ही प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में विभाग अंतर्गत श्रमिकों एवं उनके परिजनों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उन्होंने

बताया कि श्रमवीरों और उनके परिवार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देते हुए विगत दो वर्षों में 800 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है। श्रमिकों के लिए आवास निर्माण सहायता, सुरक्षा उपकरण सहायता, महतारी जतन योजना, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, नोनी सुरक्षा योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति, श्रमिक सियान सहायता योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, गणवेश एवं साइकिल वितरण जैसी सुविधाओं के साथ बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपये की मेधावी छात्रवृत्ति तथा विदेश में अध्ययन हेतु 50 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उन्होंने श्रमवीरों से अपील की कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और पारदर्शिता के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। अब योजनाओं की सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। आज भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में प्रेषित की गई है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा श्रमिक बाहुल्य जिला है, यहां बाल्को, एनटीपीसी एवं एसईसीएल जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। श्रमिकों के हित में वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु श्रमेव जयते पोर्टल एवं कॉल सेंटर संचालित है। श्रमिक इन माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। श्रम मंत्री ने उपस्थित सभी श्रमिकों से विभागीय योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने तथा अन्य श्रमिक साथियों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

संपादकीय

लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हुई थी और तब से लेकर यह प्रक्रिया विवादों में है। शुरू में चुनाव आयोग की ओर से आधार कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज में शामिल न करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। यह बात भी अहम है कि आयोग की इस कवायद में किसी राज्य सरकार का सीधे तौर पर दबाव या दखल देना उचित नहीं हो सकता।लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में समय-समय पर संशोधन जरूरी है। इसी मकसद से देश के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मगर इसमें कई तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कभी बड़ी संख्या में नागरिकों को मसविदा सूची से बाहर करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी सियासी दलों की ओर से इस प्रक्रिया में नियमों के विपरीत दखल देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि नई मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, ताकि सभी पात्र नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित रह सके और अपात्र या मृतकों के नाम सूची से हटाने का कार्य बिना किसी विवाद या बाधा के पूरा हो सके। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से जुड़े ऐसे ही एक मामले में सोमवार को सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न आशंकाओं का निराकरण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हुई थी और तब से लेकर यह प्रक्रिया विवादों में है। शुरू में चुनाव आयोग की ओर से आधार कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज में शामिल न करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। आयोग का तर्क था कि आधार को नागरिकता का पहचान पत्र नहीं माना जा सकता, मगर बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पहचान के दस्तावेज में शामिल कर लिया गया। अब पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया पर आए दिन नए-नए सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने खुद राज्य में मसविदा सूची में छूट गए मतदाताओं की सुनवाई की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया था। आयोग ने माना था कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में तकनीकी समस्या की वजह से कई लोगों के नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं और ऐसे लोगों के लिए फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं है। मगर यह बात भी उतनी ही अहम है कि आयोग की इस कवायद में किसी राज्य सरकार का सीधे तौर पर दबाव या दखल देना उचित नहीं हो सकता। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सफल तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है।

भारत की गिनती विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। विकास की यह यात्रा सड़कों, इमारतों, डिजिटल सुविधाओं, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों के आंकड़ों से मापी जाती है। मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा प्रश्न लगातार अनुत्तरित है, जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं। यह सवाल है—क्या देश की महिलाएं इस विकास यात्रा में समान रूप से सहभागी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यह मसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति की नींव से जुड़ा है। यह सच है कि हाल के वर्षों में महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या कई स्थानों पर छात्रों से अधिक है। परीक्षा परिणामों में भी वे अव्वल रहती हैं। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, जो दशकों के प्रयासों का नतीजा है। इसके बावजूद जब शिक्षा से रोजगार की ओर बढ़ने का समय आता है, तो कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम नजर आती है। यह विरोधाभास भारतीय समाज की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है।

तेज विकास, धीमी भागीदारी, डिग्री के बाद भी भारतीय महिलाएं कार्यबल से बाहर क्यों?

(सुनिधि मिश्रा)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग तैंतीस फीसद के आसपास है, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर पचपन फीसद से अधिक है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और अवसरों की असमानता का द्योतक है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। अनेक विकासशील देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी भारत से कहीं अधिक है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, पर उसका स्वरूप चिंताजनक है। अधिकांश महिलाएं कृषि, घरेलू उत्पादन या पारिवारिक श्रम में संलग्न हैं, जहां उन्हें न तो नियमित वेतन मिलता है और न ही सामाजिक सुरक्षा।

उनका श्रम आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज तो हो जाता है, मगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षित और कुशल हैं, मगर सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर रोजगार तक उनकी पहुंच सीमित है। इसके परिणामस्वरूप वे या तो अल्प वेतन पर काम करती हैं या फिर कार्यबल से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं।

महिला सशक्तीकरण के बिना राष्ट्र की समृद्धि संभव नहीं: महिलाओं की कार्यबल से दूरी सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव से भी गहराई से जुड़ी है। आज भी अधिकांश परिवारों में यह अपेक्षा बनी हुई है कि घर, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल का दायित्व मुख्यत: महिलाओं का ही है। जब काम और घर के बीच संतुलन बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले महिला को ही करिअर का त्याग करना पड़ता है।

यह त्याग स्वैच्छिक कम और परिस्थितिजन्य अधिक होता है। समाज में गहराई से बैठी यह धारणा कि महिलाओं की प्राथमिकता घर है और कार्य केवल एक विकल्प, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा है।

एक अन्य गंभीर समस्या है 'वेतन असमानता'। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन बीस-पच्चीस फीसद कम वेतन प्राप्त होता है। यह अंतर महिलाओं के आत्मविश्वास, कार्य-संतोष और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे महिलाओं की क्रय शक्ति और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।

सरकार की ओर से महिला केंद्रित अनेक कानून और

योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व लाभ, समान वेतन का अधिकार और महिला-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल है। मगर समस्या कानूनों की अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। अनेक महिलाएं आज भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, और जो जागरूक हैं, वे सामाजिक दबाव या नौकरी छूटने के भय से आवाज उठाने से परहेज करती हैं। कार्यस्थलों पर शिकायत निवारण तंत्र या तो मौजूद नहीं होते या फिर इतने कमजोर होते हैं कि महिलाएं उन पर भरोसा नहीं कर पातीं। पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में कार्यरत महिलाओं का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां न तो कार्य समय निश्चित है और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव या पारिवारिक कारणों से कार्य से विराम लेती हैं। पुनः कार्यबल में लौटना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि नियोक्ता अनुभव में आए इस अंतर को नकारात्मक रूप से देखते हैं। हालांकि कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्ष 2025 में तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि यदि नीति, इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग एक साथ आएं, तो परिवर्तन संभव है। हालांकि इन प्रयासों का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा, जब तक समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी केवल महिला सशक्तीकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बराबर की हिस्सेदारी से जुड़ा मसला भी है। विभिन्न अध्ययनों में यह बात उभर कर सामने आई है कि यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान स्तर तक पहुंच जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत अपनी जीडीपी में बीस-तीस फीसद तक की वृद्धि दर्ज कर सकता है, यदि लैंगिक अंतर को समाप्त कर दिया जाए। आज के दौर में यह जरूरी है कि कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाया जाए, जहां लचीले कार्य समय, सुरक्षित परिवहन, बाल देखभाल सुविधाएं और समान वेतन सुनिश्चित हों। साथ ही परिवार और समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि महिला का कार्य करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। पुरुषों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में समान भागीदारी निभानी होगी। जब तक यह समझ विकसित नहीं होगी, तब तक कानून कागजों में और अवसर आंकड़ों में ही सिमटे रहेंगे। कंपनियों को केवल विविधता के आंकड़े प्रस्तुत करने से आगे बढ़कर वास्तविक समावेशन की संस्कृति विकसित करनी होगी। महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण और करिअर पुनः प्रवेश कार्यक्रम आवश्यक हैं। साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियां और उनका पालन अनिवार्य है। सवाल यही है कि क्या हम महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी मानते रहेंगे, या उन्हें विकास का सक्रिय सहभागी बनाएंगे? जब तक महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सम्मान, सुरक्षा और समानता के साथ सुनिश्चित नहीं होती, तब तक यह कहना कठिन है कि भारत का विकास वास्तव में समावेशी है। कानून मौजूद हैं, वादे और घोषणाएं भी हैं, पर अब समय की मांग है कि अवसर भी उतने ही स्पष्ट, सुलभ और समान हों। यह परिवर्तन केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव से ही संभव है।

सरकारी संरक्षण से 'फूड बास्केट' बनकर उभरता उप्र

(धर्मेंद्र मलिक)

उत्तर प्रदेश आज खेती-किसानी के माध्यम से देश में नए आयाम स्थापित कर रहा है। गेहूं, गन्ना, दूध और आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ धान, केला, आम, अमरूद और मेंथा जैसे उत्पादों में भी प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान है। यह परिवर्तन केवल भौगोलिक अनुकूलताओं का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले वर्षों में लागू की गई ठोस नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय अनुशासन का परिणाम है। वर्ष 2016-17 में जहां कृषि विकास दर 8.6 प्रतिशत थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 17.7 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। देश की मात्र 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहा है। यह स्वयं में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हाल में प्रस्तुत 9,12,696 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 10,888 करोड़ रुपये कृषि एवं पशुपालन के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बिना नए कर आरोपण के राजस्व-संग्रह में वृद्धि और व्यर्थ अपव्यय की रोकथाम के माध्यम से संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया है। यह दृष्टिकोण विकास को जन-भार नहीं, बल्कि जन-सहभागिता के रूप में स्थापित करता है। 2017 में सत्ता संभालते ही सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए, जिससे लाखों किसान राहत की सांस ले सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। लगभग 3.12 करोड़ किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ पहुँचा है।

सिंचाई, ऊर्जा और भुगतान: बाणसागर, सरयू नहर, मध्य गंगा नहर और अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाओं के पूर्ण होने से लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हुई। निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली ने लागत कम की। पिछले नौ वर्षों में गन्ना किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया, जिससे भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता आई। एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बनने से चीनी मिलों की स्थिति सुधरी और किसानों के भुगतान चक्र में स्थिरता आई।

कृषि को केवल उत्पादन-केंद्रित गतिविधि मानना अब पर्याप्त नहीं है। मूल्य-संवर्धन, भंडारण, प्रसंस्करण, निर्यात और ऊर्जा-दक्षता से जुड़कर ही किसान की आय में स्थायित्व आ सकता है। जब धान चावल बने, गेहूँ आटा बने, फल जूस या प्रसंस्कृत उत्पाद बनें-तभी लाभ-श्रृंखला का बड़ा हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ठहरता है। 2,832 करोड़ रुपये का बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण पर निवेश इसी सोच का प्रतीक है।

डिजिटल और तकनीकी कृषि

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से त्वरित ऋण स्वीकृति, ड्रोन द्वारा कीटनाशक छिड़काव, एआई आधारित फसल निगरानी, सीड पार्क और विश्वस्तरीय हैचरी-ये सभी संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर तकनीक-सक्षम कृषि मॉडल की ओर अग्रसर है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषि की केंद्रीय भूमिका है। यदि उत्पादन, मूल्य-संवर्धन और निर्यात-उन्मुख संरचना का यह मॉडल स्थिरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है, तो उत्तर प्रदेश न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का आधार बनेगा, बल्कि वैश्विक खाद्य-शृंखला में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकता है। उत्तर प्रदेश अब केवल अपनी आवश्यकता पूरी करने वाला राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा विमर्श का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। लेखक- राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक)ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

दुनिया में गहरा रहा जल संकट, यूएन रिपोर्ट की डरावनी चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

बड़ा सवाल यह है कि अगर दुनिया पानी के लिहाज से दिवालिया हो गई, तो क्या होगा? रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने जो कुछ कहा है, उसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से पानी अचानक खत्म हो जाएगा, बल्कि जिस ढंग से जल का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जल व्यवस्था की रीढ़ टूटनी शुरू हो गई है। दुनिया में बढ़ता जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़े जाने की भविष्यवाणियां तक की जा चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के शोधकर्ताओं की हाल में आई एक रपट इन चिंताओं को और गंभीर रूप दे रही है।

(अमर पाल सिंह)

इसमें कहा गया है कि पिछले कई दशकों के दौरान जल के अत्यधिक दोहन, सिमटते भूजल स्रोतों, भूमि क्षरण, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उपजी बाधाओं की वजह से दुनिया अब जल संकट की अवस्था से आगे बढ़कर 'वैश्विक जल दिवालियापन' की स्थिति में कदम रख चुकी है।

जब कोई इंसान दिवालिया होता है, तो उसके पास पैसा नहीं बचता, घर तक गिरवी हो जाता है और विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि अगर दुनिया पानी के लिहाज से दिवालिया हो गई, तो क्या होगा? रपट में शोधकर्ताओं ने जो कुछ कहा है, उसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से पानी अचानक खत्म हो जाएगा, बल्कि जिस ढंग से जल का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जल व्यवस्था की रीढ़ टूटनी शुरू हो गई है।

समूचे विश्व में बहुत पहले से जल संकट की चर्चा होती रही है, मगर इसे एक ऐसे झटके की तरह देखा जाता रहा है, जिससे समय के साथ उबरा जा सकता है। अगर जल संकट के बारे में चेतावनी दी जाती रही है, तो यह भरोसा भी दिलाया जाता रहा है कि फिर से अच्छी बरसात होगी, जल का स्तर सुधर जाएगा और हालात पुनः सामान्य हो जाएंगे।

मगर नई रपट ने इस भरोसे पर सवालिया निशान लगा दिया है। रपट में साफ कहा गया है कि विश्व की जल आपूर्ति प्रणाली कई जगहों पर पतन के दौर में पहुंच चुकी है। अनेक क्षेत्रों में पानी की कमी अब स्थायी स्वरूप लेती जा रही है। यह स्थिति केवल पानी की कमी की नहीं, बल्कि व्यवस्था के टूटने की ओर संकेत करती है। ऐसे में अब हमें पानी के बारे में अपने सोचने का ढंग बदलना होगा।

अब तक जल संकट को एक अस्थायी समस्या माना जाता रहा है। अकाल पड़े, परेशानियां आईं, मगर कुछ साल बाद हालात सुधर गए। किसी साल वर्षा कम हुई, लेकिन अगले मानसून में भरपाई हो गई। जब ऐसा चल रहा था, तो नीतियों का निर्धारण भी इसी अनुरूप होता रहा। कभी जल की बूंद-बूंद को सहेजने वाले समाज ने भी लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। कई जगहों पर जलस्रोत इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें पहले जैसी स्थिति में लौटने में दशकों लग सकते हैं और कई मामलों में शायद लौटना संभव ही न हो पाए।

हम दिवालियापन को व्यक्ति के आर्थिक रूप से कंगाल होने के संदर्भ में ही समझते आए हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से दिवालिया होता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि दुनिया से पैसा खत्म हो गया है। पैसा रहता है लेकिन उस व्यक्ति की आमदनी, खर्च और कर्ज के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरह दुनिया में पानी मौजूद है, लेकिन उसकी उपलब्धता, उसके उपयोग और उसके पुनर्भरण के बीच संतुलन तेजी से टूट

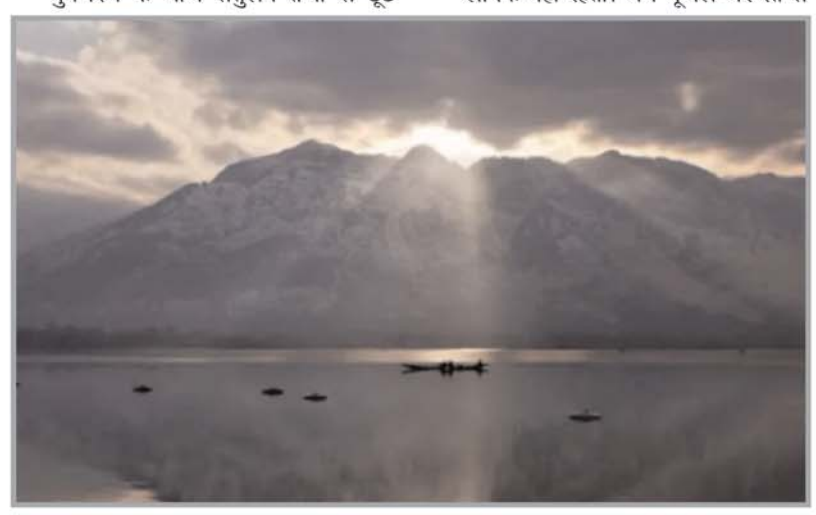

रहा है। हम भू-गर्भ से जितना पानी निकाल रहे हैं, उतना पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। यानी जल खाता खाली हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ताओं ने रपट में जो कुछ कहा है, उसके अनुसार इस असंतुलन की जड़ें दशकों पुरानी हैं। भूजल के अंधाधुंध दोहन, नदियों को गंदे नालों में बदल दिए जाने, वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर पानी की प्राकृतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। जब पानी प्रदूषित हो जाता है, तो वह मौजूद होते हुए भी उपयोग के लायक नहीं रहता। जब भूजल जरूरत से ज्यादा निकाला जाता है, तो वह वापस भरने से पहले ही खत्म हो जाता है।

धीरे-धीरे यह स्थिति एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है, जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बात भी सच है कि इस संकट का असर सब पर बराबर नहीं पड़ता। जिस प्रकार आर्थिक दिवालियापन में सबसे पहले गरीब तबके टूटते हैं, वैसे ही जल संकट और जल दिवालियापन का सबसे बड़ा बोझ भी कमजोर वर्गों पर पड़ना स्वाभाविक है। छोटे किसानों, आदिवासियों, शहरी गरीब बस्तियों, महिलाओं और युवाओं के जीवन पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जिन संपन्न एवं शक्तिशाली वर्गों ने सबसे ज्यादा पानी का दोहन किया होता है, उसके लाभ तो अक्सर उन्हीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम दूसरों को भुगतने पड़ते हैं।

भारत के संदर्भ में देखें, तो संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और भी गहरी चिंता पैदा करने वाली है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में है, पर उसके हिस्से में उपलब्ध मीठा पानी सीमित है। इसके बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो सबसे ज्यादा भूजल दोहन कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा और हर साल गहरे नलकूप खोदे जा रहे हैं। हमारी नदियों की हालत भी सबके सामने है। कई नदियां मृत कही जाने लगी हैं, तो कई अब वर्षाकाल तक सीमित हो गई हैं। शहरों में तालाब और झीलें या तो पाट दी गई हैं या गंदे पानी का भंडार बन चुकी हैं। वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है, उसे सहेजने के उपाय नहीं हो रहे। तमाम मुश्किलों के बावजूद यह तय है कि हमारे यहां पानी मौजूद है, मगर हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है, भारत में भी जल संकट प्राकृतिक से अधिक नीतिगत है। ऐसे उद्योगों की स्थापना पर चिंता व्यक्त की जा रही है, जिनमें जल खपत अत्यधिक होती है। खेती में ज्यादा सिंचाई की जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाना भी एक बड़ा कारण है। सस्ती या मुफ्त बिजली देने के निर्णयों ने भूजल दोहन को और बढ़ा दिया है। औद्योगिक और शहरी प्रदूषण ने उपलब्ध जल को अनुपयोगी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम जल संकट से पार पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मानना होगा कि पानी असीमित नहीं है। भूजल को निजी संपत्ति मानने की सोच में बदलाव लाना होगा। भूगर्भ में मौजूद पानी सामूहिक धरोहर है और उसकी रक्षा करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल संकट और खेती के बीच गहरा संबंध है। हमें खेती में फसलों के चयन को पानी की उपलब्धता से जोड़ना होगा। शहरों और गांवों में जल की बचत को औपचारिकता भर से ऊपर उठकर और जरूरत बनाकर काम करना होगा। गंदे पानी को बहाने की जगह उसे साफ करके पुनः उपयोग में लाने के काम को बढ़ावा देना होगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि यह सब करेगा कौन? केवल सरकारों पर जिम्मेदारी डाल कर इस संकट से नहीं उबरा जा सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि जल है तो कल है।

ग्रामीण आस्था, खेल भावना और जनसहभागिता का अनूठा संगम

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पेरमापाल में दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता सम्पन्न

कोण्डागांव । सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क सुदृढ़ करने के उद्देश्य से थाना बयानार क्षेत्र के ग्राम पेरमापाल में 16 एवं 17 फरवरी को दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डॉडे एवं उप पुलिस अधीक्षक सतीश भार्गव के संरक्षण में संपन्न हुआ। आयोजन का नेतृत्व थाना प्रभारी बयानार राकेश कुमार राठौर ने किया। 17 फरवरी को समापन समारोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डॉडे, उप पुलिस अधीक्षक सतीश भार्गव तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पेरमापाल के सरपंच दसरू नेताम, फूल सिंह कोराम, माटी पुजारी तिजू राम कोर्राम, ग्राम पटेल बज्जू राम कोर्राम, गायता पट्टू राम कोर्राम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आसपास के ग्रामों–रेंगागोंदी, बयानार, केजंग, मुंगवाल, चेरंग एवं नरिहा–के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई। ग्रामीणों की आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता के पूर्व कुलदेवी-देवताओं की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक मांदरी नृत्य दल द्वारा किया गया, जिससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी घुल गया।16 टीमों ने लिया हिस्सा-प्रतियोगिता में ग्राम पेरमापाल, मुंगवाल, चेमा, रेंगागोंदी, आदनार, केजंग, कोरोहबेडा, चेरांग, जोगी अलवाड, तोतर, आमगांव, बयानार एवं मढ़नार सहित कुल 16 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार-प्रथम पुरस्कार - शील्ड, जर्सी एवं 5000 द्वितीय पुरस्कार - शील्ड, जर्सी एवं 3000तृतीय पुरस्कार - शील्ड, जर्सी एवं 2000चतुर्थ पुरस्कार - वॉलीबॉल, नेट एवं 1000प्रतियोगिता में ग्राम आमगांव की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर ग्राम मुंगवाल 'ए', तृतीय स्थान पर ग्राम आदनार तथा चतुर्थ स्थान पर मुंगवाल 'बी' की टीम रही।महिलाओं का सम्मान- कार्यक्रम के दौरान ग्राम पेरमापाल की 20 महिलाओं को साड़ी वितरण कर सम्मानित किया गया। इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और पुलिस विभाग के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना व्यक्त की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ते हैं तथा पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। आयोजन ने खेल, संस्कृति और सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

कोण्डागांव को मिला नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, टिकट काउंटर का शुभारंभ

नए परिसर से होगा बसों का संचालन, शहर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

कोण्डागांव। शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कोण्डागांव में नगरपालिका अध्यक्ष नरपती पटेल की उपस्थिति में बस टिकट काउंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बस संचालकों को कॉम्प्लेक्स भवन की चाबी भी सौंपी गई। साथ ही बस स्टैंड परिसर में 8 नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ।

नगरीय प्रशासन के अनुसार अब सभी बसों का नियमित संचालन नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से किया जाएगा। पुराना बस स्टैंड बसों के ठहराव के लिए उपयोग में नहीं रहेगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों–रायपुर नाका, जय स्तंभ चौक, चौपाटी एवं बंधा तालाब के समीप निर्धारित समय पर बसों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। रात्रिकालीन समय में सुमित बाजार के पास भी अल्पकालीन ठहराव की व्यवस्था की गई है, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बस संचालकों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार रुपए और दूसरी बार 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष नरपती पटेल ने कहा कि नए बस स्टैंड से बस सेवा प्रारंभ होने से शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिलेगी। यह पहल सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था और आधुनिक शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।बस स्टैंड परिसर में प्रस्तावित 8 नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण से स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगरीय प्रशासन ने नागरिकों से नई व्यवस्था का पालन करने तथा नए बस स्टैंड से बस सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है, ताकि शहर में सुचारू यातायात एवं बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।कार्यक्रम में एसडीएम अजय उराव, परिवहन अधिकारी अतुल असैया, यातायात प्रभारी मुकेश जोशी, तहसीलदार मनोज रावटे, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश डे सहित पार्षदगण, बस संचालक एवं नागरिक उपस्थित रहे।

बोड़नपाल 01 में कहानी कथन उत्सव का आयोजन बच्चों ने दिखाया अपनी प्रतिभा का जलवा

बस्तर। बस्तर विकास खंड के बोड़नपाल 01 में संकुल स्तरीय कहानी कथन उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में दीप प्रज्वालन के साथ हुई, जिसने समारोह को एक पवित्र और उत्साही माहौल प्रदान किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा और कलात्मकता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा, समूह में कहानियां सुनी, लिखी और चित्र बनाकर रंग भरे, जिससे उनकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिला।कहानी कथन उत्सव का उद्देश्य बच्चों को भाषा और ज्ञान की विशाल संसार से जोड़ना था, जिससे उनकी शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता विकसित हो। कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच रायमती मौर्य, उपसरपंच सुकलाल बघेल, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक मोतीलाल श्वेता, संकुल समन्वयक देवेंद्र ठाकुर, शिवराम मौर्य, मालती कच्छ, गायत्री बघेल, पुष्पा बघेल, मंगलू बघेल, पवन साय, पियासी बघेल, विनय मिंज, गजेंद्र पांडे, पुलकित बघेल, लखमू बघेल, भारती सर, लईखान कश्यप, धनसिंह बघेल, चिंतामणि बघेल, पुरुषोत्तम पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सुझावित बातों को भी साझा किया गया, जिसमें स्थानीय समुदाय का ज्ञान, लोक परंपराएं, संस्कृति, शिल्प, हस्तकला और जीवन कौशल को स्कूल शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया। इससे बच्चों को अपने आसपास के वातावरण और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिला।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की समीक्षा बैठक में मेम्बरशिप ग्रोथ पर जोर

कबीरधाम के अजय चंद्रवंशी जम्बूरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित

कोण्डागांव।गभारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ की जिला संगठन आयुक्तों की समीक्षा बैठक मंगलवार को रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने की। बैठक में राज्य कोषाध्यक्ष हेमंत देवांगन की विशेष उपस्थिति रही। बैठक में जिलों के कार्यों की निर्धारित एजेंडा के अनुसार वन-टू-वन समीक्षा की गई। कबीरधाम जिले से जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) अजय चंद्रवंशी शामिल हुए। जिला संगठन आयुक्तों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में अर्जित अंशदान की जानकारी प्रस्तुत की।

राज्य मुख्य आयुक्त श्री खालसा ने शत-प्रतिशत शासकीय विद्यालयों से अंशदान जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामी आत्मानंद विद्यालयों एवं अधिक से अधिक निजी विद्यालयों को भी स्काउट-गाइड गतिविधियों से जोडने पर बल दिया। उन्होंने ऑनलाइन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर या आईटी जानकार लीडर्स, रोवर्स एवं रेंजर्स का सहयोग लेने की बात कही। बैठक में जिलों में सक्रिय लीडर्स की स्थिति, सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में आयोजित बेसिक कोर्स, कोर्स उपरांत प्रारंभ की गई नई यूनिट्स, आगामी सत्र की कार्ययोजना, जिला वार्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मेम्बरशिप ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिला डैशबोर्ड, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में सहभागिता तथा आय-व्यय की समीक्षा की गई। इस अवसर पर 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ तथा बालोद में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी में सहभागिता की भी समीक्षा की गई। जम्बूरी कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला संगठन आयुक्तों को सम्मानित किया गया, जिसमें कबीरधाम जिले से अजय चंद्रवंशी को सम्मान प्रदान किया गया। राज्य मुख्य आयुक्त ने कमजोर प्रदर्शन वाले कुछ जिलों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी तथा जिला संगठन आयुक्तों से कामकाज में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही जिला संगठन आयुक्तों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समिति गठन की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के साथ स्काउटिंग को गुणवत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़ाते हुए देशभर में छत्तीसगढ़ की एक सक्रिय एवं क्रियाशील छवि स्थापित करना लक्ष्य है। बैठक का संचालन प्रभारी राज्य सचिव सरिता पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर संयुक्त राज्य सचिव बीना यादव, स्टेट कॉर्डिनेटर (मेम्बरशिप ग्रोथ) मोहम्मद सादिक शेख, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) अमित क्षत्रिय, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) पूनम साहू एवं जलवती साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतियोगिता शुरू, पहले मैच में उत्तर प्रदेश ने गंगालूर को हराया

बीजापुर में वॉलीबॉल का बड़ा आयोजन, देशभर की टीमें ले रहीं हिस्सा

बीजापुर। जिले के मिनी स्टेडियम में बिते बुधवार से अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस तीन दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के चलते शहर में खेल प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में इनकम टैक्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जबलपुर रेलवे, छत्तीसगढ़ पुलिस, साई तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना की टीमें मैदान में उतरी हैं। पहले दिन से ही मुकाबले तेज और प्रतिस्पर्धी नजर आए। खिलाड़ियों के दमदार सर्व, मजबूत ब्लॉक और आक्रामक स्मैश ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं वॉलीबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश गागड़ा, जिला पंचायत की सीईओ नम्रता चौबे, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी और मथियास कुजूर, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, जिला खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल तथा एसडीएम जागेश्वर कौशल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।उद्घाटन मुकाबला गंगालूर और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन अंत में उत्तर प्रदेश ने जीत दर्ज की। खिलाड़ियों की ऊर्जा और तालमेल ने संकेत दे दिया है कि आने वाले मुकाबले और भी दिलचस्प होंगे।आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है।

समग्र शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल से बहुदिव्यांग छात्रा गुंजन को मिली नई राह

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला सलिहापारा तुएगुहन की कक्षा दूसरी की बहुदिव्यांग छात्रा कु. गुंजन सुरेंद्र को आज समग्र शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में व्हीलचेयर एवं एमआर किट प्रदान की गई।समग्र शिक्षा विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। दोनों विभागों के समन्वित प्रयास से गुंजन को यह आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे अब वह नियमित रूप से विद्यालय आ-जा सकेगी। व्हीलचेयर मिलने से छात्रा के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पूर्व में परिजनों को उसे गोद में उठाकर विद्यालय लाना पड़ता था, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस सुविधा से न केवल पढ़ाई सुचारु होगी, बल्कि छात्रा का आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक कला के संगम से गुंज उठा 'नियाग्रा' का तट

जगदलपुर। विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के समीप मेला स्थल में बुधवार को 'चित्रकोट महोत्सव 2026' का शानदार आगाज़ हुआ, जहाँ बस्तर की माटी की सोंधी खुशबू और लोक कलाओं के विविध रंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्रकोट महोत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की दिशा में सरकार प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा सांस्कृतिक, कला और खेल गतिविधि के माध्यम पर्यटन स्थल में चित्रकोट महोत्सव को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

नूकनपाल में सीआरपीएफका सिविक एक्शन आयोजित, ग्रामीणों को मिली जरूरत की सामग्री

बीजापुर। जिले के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा के साथ लोगों का भरोसा जीतने के लिए बी/62 वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नूकानपाल में सिविक एक्शन कार्यक्रम किया। इसमें आसपास के कई गांवों से पहुंचे जरूरतमंद ग्रामीणों और बच्चों को रोजमर्रा के काम आने वाली सामग्री दी गई।कार्यक्रम पुलिस उप महानिरीक्षक बी.एस. नेगी और कमांडेंट दीपक मेहरा के मार्गदर्शन में हुआ। सहायक कमांडेंट अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में नूकानपाल, धाराभम, बोदल-पुंगर, भुसगुड़ी और होसुरपाल के ग्रामीण शामिल हुए।इस दौरान कंबल, सोलर लैंप, खेल सामग्री, पढ़ाई का सामान और कृषि से जुड़ी वस्तुएं बांटी गईं। अधिकारियों ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और इलाके में शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से गांवों के साथ जुड़ाव बढ़ता है और विकास की राह आसान होती है।

रोफरा ग्राम खमढोड़गी में 12 दिवसीय सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ

कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कांकेर जिले के रोफरा ग्राम खमढोड़गी, ग्राम पंचायत कोकपुर में 12 दिवसीय सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।कांकेर जिला, जो अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, वनोपज, कृषि आधारित संसाधनों एवं पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाता है, वहां उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों–जैसे लघु वनोपज प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, बांस एवं लकड़ी शिल्प, साथ ही सेवा क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए युवाओं एवं महिलाओं की उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक भागीदारी देखने को मिली। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि÷कांकेर जैसे आकांक्षी जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला उद्यमी बन सकता है, बस उसे सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की जरूरत है। कार्यक्रम प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को उद्यम स्थापना की संपूर्ण प्रक्रिया, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, बैंक ऋण प्रक्रिया, शासकीय योजनाओं की जानकारी, विपणन प्रबंधन, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लागत निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं पारंपरिक हुनर को बाजार से जोड़ने की रणनीति पर विशेष फोकस किया जाएगा।कार्यक्रम में महिलाओं को विशेष रूप से घर-आधारित लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया।

संक्षिप्त समाचार

मस्तूरी के 8 ग्रामों में राशन दुकान आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित, 13 मार्च तक करें आवेदन

बिलासपुर। जिले के विकासखंड मस्तूरी के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 8 ग्रामों में उचित मूल्य (राशन) दुकानों के संचालन हेतु 13 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बूढ़ीखार, गतोरा, केवतरा, गोडाडीह, मस्तूरी, मटिया, शिवटिकारी एवं सुकुलकारी ग्रामों में राशन दुकान खोले जाने हैं। इन ग्रामों राशन दुकान के लिए पात्र स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत अथवा सहकारी संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन मस्तूरी स्थित एसडीएम कार्यालय की खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक जमा करना होगा। आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में तैयार कर ए-4 आकार के लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। खाद्य निरीक्षक ने पात्र संस्थाओं से समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। विस्तृत जानकारी एसडीएम कार्यालय मस्तूरी के खाद्य शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

शासकीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा समय सारणी जारी

बिलासपुर। जिले में संचालित शासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालय हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत 1लीं से 7वीं, 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली से चौथी कक्षा की वार्षिक परीक्षा 27 मार्च से, छठवीं, सातवीं, नवमी एवं ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा 25 मार्च से प्रारंभ होगी। नवमी एवं ग्यारहवीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक वहीं शेष कक्षाओं की परीक्षा 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। कक्षाओं के अनुरूप वार्षिक परीक्षा का समय भिन्न-भिन्न निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी विषयों की प्रयोजना कार्य 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। परीक्षा उपरांत विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें एवं मध्यान्ह भोजन का सुचारू रूप से संचालन हो।

पीएम आशा योजना के तहत किसानों का पंजीयन 28 तक

बिलासपुर। जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना (पी.एम. आशा योजना) के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाना है। योजना अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर, एवं सरसों फसलों की बुवाई करने वाले किसान अपना पंजीयन 28 फरवरी 2026 तक करवा सकते है। इन फसलों की बुवाई करने वाले कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर किसान डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल पर पंजीयन करवा सकते है। पीएम आशा योजना अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों फसल प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिलें के चिन्हाकिंत केन्द्रीय एजेंसी भारती राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इस योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमें चना-5875 रू. मसूर-7000 रू. एवं सरसों-6500 रू. न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल तय किया गया है। शासन द्वारा जिलें में उपार्जन एवं भंडारण के लिए उपार्जन केन्द्र के रूप में विकासखण्ड बिल्हा से सेवा सहकारी समिति-बिल्हा, सेंदरी सम्बद्ध भंडारण केन्द्र-बिलासपुर विकासखण्ड-मस्तुरी से सेवा सहकारी समिति जयरामनगर, सम्बद्ध भंडारण केन्द्र-जयरामनगर विकासखण्ड-तखतपुर से सेवा सहकारी समिति तखतपुर सम्बद्ध भंडारण केन्द्र-तखतपुर तथा विकास खण्ड-कोटा से सेवा सहकारी समिति कोटा सम्बद्ध भंडारण केन्द्र-बिलासपुर का चयन एवं अधिसूचित किए गए है। कृषकों से फसल उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) किया जाएगा। योजना अन्तर्गत शासन द्वारा पंजीकृत कृषकों से रबी फसल चना 6 क्विंटल, मसूर-2 क्विंटल एवं सरसों 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। किसान भाईयों से अपील है कि अपने क्षेत्र के संबंधित समिति में पंजीयन कराते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का विक्रय कर सकते है।

नशे में धुत युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई

कोरबा। कोरबा में देर रात तेज रफ्तार और शराब के नशे ने बड़ा हादसा करा दिया। मानिकपुर चैकी क्षेत्र के अंतर्गत घंटाघर-मिनिमाता कॉलेज मुख्य मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि एयरबैग खुलने से चालक और उसके साथ सवार युवक की जान बच गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात कुछ युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। शहर के व्यस्त मार्ग पर भी वे वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सके।

ब्राह्मण मातृशक्ति परिषद् ने कराया 31 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार

बिलासपुर। उत्कृष्ट ब्राह्मण सामाजिक संगठन समग्र ब्राह्मण परिषद् छत्तीसगढ़ की बिलासपुर मातृशक्ति परिषद् ईकाई द्वारा गुरुवार को महामाया देवी की नगरी रतनपुर में मंदिर परिसर के श्री सत्संग मंडप में 31 ब्राह्मण बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार कराया गया. समग्र ब्राह्मण मातृशक्ति परिषद् बिलासपुर की जिलाध्यक्ष श्रीमती रमा दीवान एवं जिला सचिव श्रीमती अंजू शर्मा ने आयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि संगठन की जिला ईकाई द्वारा पहली बार रतनपुर में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया है. 19 फरवरी को विशेष रूप से उपनयन संस्कार का शुभ एवं शुद्ध मुहूर्त की तिथि में 31 ब्राह्मण बटुकों को जनेऊ धारण करवाया गया. सनातन धर्म में कुल सोलह संस्कार होते हैं इसमें उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार को दसवां स्थान प्राप्त है. इस संस्कार के अंतर्गत ही व्यक्ति को जनेऊ पहनाई जाती है. इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है. उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है खुद को अंधकार से दूर रखना और प्रकाश की ओर बढ़ना. जनेऊ के पवित्र धागे को व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़े रखते हैं. वह बुरे कर्म, बुरे विचारों से दूर रहता है. यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने वाले को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. यही वजह है कि सनातन धर्म में जनेऊ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है. आचार्यों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान के साथ तैयार मंडप में सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद वैदिक रीति रिवाज एवं प्रचलित परंपरानुसार के अनुसार इस कार्यक्रम में सबसे पहले तेलमाटी, मंडपाच्छादन, हरिद्रालेपन, चिकट, मातृका पूजन हुआ इसके बाद उपनयन संस्कार के लिये उपस्थित सभी बटुकों का मुंडन करवाया गया. पुन: स्नान के बाद सभी बटुकों ने आठ ब्राह्मणों के साथ भोजन कर अष्ट ब्राह्मण भोज की विधि संपन्न की. इसके बाद आचार्यों ने पलाश दंड पकड़े हुए बटुकों को जनेऊ धारण करवाकर भगवान सूर्यनारायण का दर्शन करवाया. तत्पश्चात् ब्राह्मणों द्वारा प्रत्येक बटुक को कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गयी. शिक्षा के अंतर्गत बताया गया कि जनेऊ के बाद किन-किन नियमों का पालन करना है. इसके बाद बाद बटुकों ने आयोजन में उपस्थित सभी स्वजनों से भवति भिक्षां देहि कहते हुये भिक्षा मांगी. संस्कार प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी बटुकों ने नये वस्त्र धारण किये, उसके बाद श्री मंदिर परिसर में ही धूमधाम से आतिशबाजी एवं गाजे-बाजे के साथ उनकी बारात निकाली गयी. पूजा में बटुकों के प्रतिनिधि यजमान ?के रुप में ?श्रीमती शशि द्विवेदी एवं पं.राघवेन्द्र द्विवेदी जी पूजन की प्रक्रिया संपन्न की. सामूहिक जनेऊ संस्कार का उद्देश्य समाज में धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना तथा नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे, ताकि समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता बनी रहे. संगठन की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला तिवारी एवं प्रदेश सचिव सजल तिवारी द्वारा जानकारी दी गयी कि जब माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, तब दीक्षा दी जाती थी. सनातन धर्म में दिशाहीन जीवन को एक दिशा देना ही दीक्षा माना जाता है. दीक्षा का अर्थ संकल्प है. किसी भी व्यक्ति को दीक्षा देने का अर्थ दूसरा जन्म और व्यक्तित्व देना है. वैदिक आचार्यों के निर्देशन में मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया गया. सामूहिक उपनयन संस्कार के माध्यम से बटुकों को सनातन परंपरा, वेदाध्ययन और नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प दिलाया गया. कार्यक्रम स्थल पर धार्मिक वातावरण बना रहा और उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की. मातृशक्ति परिषद् की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज तिवारी एवं प्रदेश संगठन विस्तार प्रमुख श्रीमती उमा शुक्ला ने बताया कि संगठन द्वारा उपनयन संस्कार के सफ्लतम आयोजन का यह पहला वर्ष है.

विधायक अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की तथा जनहित के मुद्दों पर आवश्यक निर्देश दिए.....

बिलासपुर। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने आज बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की तथा जनहित के मुद्दों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस क्रम में बिलासपुर के टिकरापारा क्षेत्र में अटल वाटिका भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हुए श्री अग्रवाल ने सामुदायिक भवन में निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी जी, वार्ड के पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह भवन क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पश्चात उन्होंने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में आयोजित तरंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दो स्मार्ट बोर्ड का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। विधायक अमर अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। इसके अतिरिक्त, अपने निवास कार्यालय में आयोजित अपनों से मुलाकात कार्यक्रम के दौरान श्री अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं विकास उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आमजन को शीघ्र राहत दिलाने के लिए सतत प्रयास जारी रहेंगे।

साइबर फ्रॉड के मामले में आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए.....

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का मैसेज भेज कर फ्रॉड किया गया था। आरोपी ने प्रार्थी के बैंक खाते से अलग-अलग कुल 3,74,000 निकाल लिया था।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी महेंद्र कुमार त्रिपाठी निवासी संजय कॉलोनी बलौदाबाजार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12.12.2025 को इसके मोबाइल नंबर पर आरोपी मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया, जिसे प्रार्थी द्वारा डिलीट कर दिया गया। उसके बाद पुन: दिनांक 14.12.2025 को मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें डियर कस्टमर इस योर वन टाइम पासवर्ड प्लीज एंटर एवं प्रोसीड थैंक यू, टीम जिओ फाइनेंस लिखा हुआ था। इसके बाद प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक गार्डन चौक बलौदाबाजार स्थित बैंक खाता से 04 बार में कुल 3,74,000 निकल जाने का मैसेज प्राप्त हुआ। प्रार्थी के बैंक खाता से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मैसेज आदि भेज कर 3,74,000 निकालते हुए साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है। कि रिपोर्ट पर धारा 318(4) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जांच कार्यवाही करते हुए आरोपी द्वारा प्रार्थी के मोबाइल में भेजे गए मैसेज एवं स्टेट बैंक बलौदाबाजार से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर तकनीकी विश्लेषण करते हुए कोलकाता से आरोपी शौविक राजवंशी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सोदपुर इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 112 थाना खोरदा जिला नाथ 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को मैसेज भेजते हुए धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि उसके बंधन बैंक स्थित खाते में धोखाधड़ी की रकम जमा होती है, जिसके बदले में उसे कमीशन के रूप में पैसा प्राप्त होता।

रतनपुर में 8 कछुओं की संदिग्ध मौत,शिकार की आशंका बताई

बिलासपुर । धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर के कुंड और बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर के तालाब में कछुओं की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई है। बुधवार सुबह बूढ़ा महादेव मंदिर के पास स्थित तालाब में एक साथ 8 कछुओं के शव पानी में तैरते मिले। इससे पहले महामाया मंदिर कुंड में भी 2 कछुओं की मौत हो चुकी है। बीते छह दिनों में कुल 10 कछुओं की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरुनी चोट के संकेत

दो कछुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें अंदरुनी चोट के निशान पाए गए हैं। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कछुओं को लाठी या किसी भारी वस्तु से पीट-पीटकर मारा गया है। मृत कछुओं की उम्र लगभग चार से पांच महीने बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विभाग की टीम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। वन अधिकारियों के अनुसार कछुए अनुसूची-एक के संरक्षित वन्यजीव हैं, जिनकी हत्या गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। यदि शिकार या सुनियोजित हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि संरक्षित वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बीसी सखियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ

महिलाएं होंगी डिजिटल सेवाओं की नई आधारशिला

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले के बीसी सखियों के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत के सीईओ मुकेश रावटे की विशेष गरिमामयी रही। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल बीसी सखियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट बैंकिंग एवं नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण में कुल 49 बीसी सखियों ने सक्रिय सहभागिता की। सीएससी आईडी प्राप्त होने के पश्चात बीसी सखियां बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के साथ विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करेंगी। इनमें मजदूर पंजीयन, बैंक खाता खोलना, बैंकिंग लेन-देन, एग्री स्टैक पंजीकरण, पासपोर्ट आवेदन, टेली-लॉ सेवा, पीएम ई-केवाईसी, पीएम किसान नया पंजीयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा जैसी जनकल्याणकारी सेवाएं शामिल हैं। ग्राम स्तर पर इन सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीणों को अब जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही सेवाओं की पारदर्शिता और त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों की कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आईडी आवेदन एवं जनरेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शीघ्र ही सभी बीसी सखियों को उनकी सीएससी आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वे अपने-अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं प्रारंभ कर सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदीप कुमार राज्य कार्यालय सीएससी बीमा सेवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सीएससी पोर्टल संचालन, आईडी आवेदन प्रक्रिया, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं सेवा संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में डीपीएम विनीत दुबे एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला टीम का विशेष योगदान रहा। टीम ने समन्वय, मार्गदर्शन एवं व्यवस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रामसर मान्यता के पश्चात आर्द्रभूमि प्रबंधन की चुनौतियां एवं अवसर

बिलासपुर - छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में स्थित कोपरा जलाशय आज केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में उभरती हुई प्राकृतिक धरोहर है। राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि के रूप में यह स्थल पारिस्थितिकी संरक्षण, जल सुरक्षा, जैव विविधता संवर्धन तथा ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामसर मान्यता किसी भी आर्द्रभूमि के लिए केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग तथा दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रबंधन का वैश्विक दायित्व भी निर्धारित करती है। इसलिए कोपरा जलाशय को एक आदर्श मॉडल आर्द्रभूमि के रूप में विकसित करने हेतु वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

पारिस्थितिक महत्व एवं जैव विविधता संरक्षण

कोपरा जलाशय जलीय तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाएँ एक साथ संचालित होती हैं, जो क्षेत्रीय पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस आर्द्रभूमि में— देशी एवं प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ शीतकालीन प्रवास के दौरान निवास करती हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप तथा जलीय जीव समुदाय पाए जाते हैं। जलकुंभी, कास, नलखाद तथा अन्य जलीय वनस्पतियाँ पोषक तत्व चक्रण में सहायक होती हैं।यह प्राकृतिक रूप से जल शुद्धीकरण, भूजल पुनर्भरण तथा बाढ़ नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करती है।

आवश्यक संरक्षण उपाय- प्रतिवर्ष पक्षी गणना एवं जैव विविधता आकलन कार्यक्रम। संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु संरक्षित मूल क्षेत्र (कोर क्षेत्र) का निर्धारण। बाह्य आक्रामक वनस्पति एवं जीव प्रजातियों का नियंत्रण। जल गुणवत्ता की नियमित जाँच—अम्लीयता स्तर, घुलित ऑक्सीजन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग तथा पोषक तत्व भार का मूल्यांकन। यदि दीर्घकालिक वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली विकसित की जाए तो यह स्थल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

जल संतुलन एवं जल संसाधन प्रबंधन-किसी भी आर्द्रभूमि का अस्तित्व उसके जल पर निर्भर करता है। जल स्तर में उतार-चढ़ाव, तलछट संचयन तथा पोषक तत्वों की अधिकता पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

प्रमुख रणनीतियाँ- जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना लागू करना। ऊपरी कृषि क्षेत्रों से रासायनिक अपवाह को नियंत्रित करना। वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण। वैज्ञानिक आधार पर तलछट निष्कासन योजना तैयार करना। संतुलित जल प्रवाह और स्वच्छ जल गुणवत्ता इस आर्द्रभूमि की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

प्रदूषण नियंत्रण एवं भूमि उपयोग प्रबंधन-तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार तथा कृषि तीव्रता के कारण आर्द्रभूमियाँ प्रदूषण और अतिक्रमण के दबाव में आ रही हैं। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो जलाशय की पारिस्थितिक क्षमता प्रभावित हो सकती है।

आवश्यक कदम- सीवेज तथा ठोस अपशिष्ट के प्रत्यक्ष जल निर्वहन पर पूर्ण प्रतिबंध। परिधीय संरक्षित क्षेत्र (बफर क्षेत्र) का निर्धारण। हरित पट्टी विकसित कर प्राकृतिक अवरोध तैयार करना। अवैध भूमि परिवर्तन एवं अतिक्रमण पर कठोर निगरानी। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहन। नीति स्तर पर इसे सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा घोषित करना संरक्षण प्रयासों को मजबूत आधार प्रदान कर सकता है।

स्थानीय समुदाय की सहभागिता- आर्द्रभूमि संरक्षण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है।

क्या एप्पल साइडर विनेगर सेहत को पहुंचाता है नुकसान?

एप्पल साइडर विनेगर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। परफेक्ट फिगर से लेकर चमकदार स्किन पाने के लिए लोग इसका सेवन कर रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर को कुछ लोग वजन कम करने के लिए सुबह-सवेरे खाली पेट भी पी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं रोजाना एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। एप्पल साइडर विनेगर का लंबे समय तक सेवन करने से आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है, जिसका लिमिट से ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर का फायदा लेना है तो उसका सेवन पर्याप्त मात्रा में ही करने की सलाह दी जाती है। एप्पल साइडर विनेगर के नुकसान क्या-क्या हैं?

दांतों की समस्या

एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, यह ऐसे तो नुकसादायक नहीं लगता है। लेकिन इसका हद से ज्यादा सेवन करना आपके दांत खराब कर सकता है। दांतों पर एक लेयर होती है, जो लिमिट से ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से हट सकती है। लेयर हटने से दांतों में सेंसटिविटी और सड़न जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको अपने दांतों से प्यार है तो एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिलाकर और स्ट्रा से पी सकते हैं।

दवाइयों पर असर

अगर आपकी किसी तरह की दवा चल रही है, तो एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते समय ज्यादा सावधानी की जरूरत है। क्योंकि इसमें मौजूद एसिड, दवाइयों के असर पर प्रभाव डाल सकता है। जिससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप किसी तरह की दवा ले रही हैं और एप्पल साइडर विनेगर को भी अपने रूटीन में शामिल करने के बारे में सोच रही हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए।

पेट की समस्या

एप्पल साइडर विनेगर को डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका लिमिट से ज्यादा सेवनपेट की समस्या हो सकती है। बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड का सेवन करने से आपके पेट में जलन हो सकती है। खासकर, अगर आपका गट सेंसिटिव, खट्टे डकार या एसिडिटी की समस्या रहती है तो एप्पल साइडर विनेगर को एक लिमिट में ही लेना चाहिए।

स्किन इरिटेशन

एप्पल साइडर विनेगर का स्किन केयर ट्रीटमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, इसे स्किन पर डायरेक्ट लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे जलन और इरिटेशन की समस्या हो सकती है। स्किन के लिए एसिड बहुत हार्ड हो सकता है, ऐसे में इसे डायलियूट करके ही लगाएं। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का टोनर या एक्ने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो पहले थोड़े एरिया पर लगाकर चेक करें।

हड्डियों पर असर

क्या आप जानती हैं एप्पल साइडर विनेगर का बहुत ज्यादा सेवन करने से आपकी हड्डियों पर असर पड़ सकता है? एप्पल साइडर विनेगर का लिमिट से ज्यादा सेवन, शरीर में पोटेशियम की मात्रा को कम करने से लिंक हो सकता है जिसकी वजह से बोन डेनसिटी भी समय के साथ कम हो सकती है। ऐसे में एप्पल साइडर विनेगर का लिमिट में ही सेवन करना चाहिए।

एप्पल साइडर विनेगर के फायदे अनेक हैं, लेकिन किसी भी चीज का अति में सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान, दोनों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से किसी तरह का रिएक्शन होता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

वैरिकोज वेंस या स्पाइडर वेंस नसों से जुड़ी समस्या है। वैरिकोज वेंस ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं होती हैं लेकिन कई बार ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। वैरिकोज वेंस हाथ, पैर, एड़ी, टखने और पंजों में ज्यादा दिखाई देती हैं। इस स्थिति में नीली नसें या नसों के गुच्छे साफ नजर आने लगते हैं। अधिकतर मामलों में लोगों को वैरिकोज वेंस की समस्या में दर्द नहीं होता है लेकिन कई लोगों के लिए यह दर्द, खड़े होने में परेशानी और जलन जैसी परेशानी की वजह हो सकती है। अगर आपको भी वैरिकोज वेंस की समस्या है, तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके आप इस समस्या से राहत पा सकती हैं।

लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके वैरिकोज वेंस की समस्या से पा सकते हैं राहत

वैरिकोज वेंस या स्पाइडर वेंस नसों से जुड़ी समस्या है। वैरिकोज वेंस ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं होती हैं लेकिन कई बार ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। वैरिकोज वेंस हाथ, पैर, एड़ी, टखने और पंजों में ज्यादा दिखाई देती हैं। इस स्थिति में नीली नसें या नसों के गुच्छे साफ नजर आने लगते हैं। अधिकतर मामलों में लोगों को वैरिकोज वेंस की समस्या में दर्द नहीं होता है लेकिन कई लोगों के लिए यह दर्द, खड़े होने में परेशानी और जलन जैसी परेशानी की वजह हो सकती है।

कई बार इन नसों में ब्लीडिंग भी हो जाती है। वैरिकोज वेंस के कारण क्या हैं और किन आसान तरीकों की मदद से इन्हें मैनेज किया जा सकता है।

इस बारे में हमने डाइटीशियन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से बात की और उनसे इसे मैनेज करने के कुछ टिप्स जानें। आइए आपको बताते हैं।

वैरिकोज वेंस के कारण

- लंबे वक्त तक खड़े रहना
- वजन अधिक होना
- प्रेग्नेंसी
- नसों पर अधिक दबाव
- हार्मोनल इंबैलेंस
- बढ़ती उम्र

इस बात का ख्याल

पुराने वक्त में घरों में खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग होता था। महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी लेकिन आज के वक्त में खड़े रहकर ही खाना बनाया जाता है। ये भी वैरिकोज वेंस की एक बड़ी वजह है। जब महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी तो वे लंबे वक्त तक खड़ी नहीं रहती थी जिससे वैरिकोज वेंस की समस्या कम देखने को मिलती थी। इससे पेल्विक मसल्स को भी फायदा होता था।

इन टिप्स को करें फॉलो

- अगर आपको वैरिकोज वेंस की समस्या है तो कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके आप इसे मैनेज कर सकती हैं।
- लंबे समय तक खड़ी ना रहें। कुछ देर खड़ी रहने के बाद बैठ जाएं।
- पैरों पर अधिक प्रेशर न डालें।
- अगर आपका वजन अधिक है तो इसे कम करने की कोशिश करें।
- ज्यादा पानी पिएं।
- अपनी डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें।
- डॉक्टर से सलाह लेकर कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। इससे वैरिकोज वेंस को बढ़ने से रोका जा सकता है।
- अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर करवाएं।

वैरिकोज वेंस होने पर न करें ये 5 काम, बढ़ सकती है मुश्किल

वैरिकोज वेंस या स्पाइडर वेंस नसों से जुड़ी समस्या है। यह कई कारणों से हो सकती हैं। अगर आपको यह समस्या है, तो कुछ कामों को करने से बचें वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

वेरिकोज वेंस के बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन, यह नसों से जुड़ी एक समस्या है। आपने कुछ लोगों के हाथ, पैर, एड़ी, पंजे या टखनों में नीली नसे या नसों के गुच्छे देखे होंगे। ये वेरिकोज वेंस होती हैं। इन्हें स्पाइडर वेंस भी कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और यह समस्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन, कई बार ये मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। इनकी वजह से कई बार, टांगों में खून की सप्लाई पर असर होता है। कई लोगों को इनकी वजह से खड़े होने में परेशानी हो सकती है। वहीं, कई बार इनमें दर्द और जलन भी होती है। अगर आपको यह समस्या है, तो आपको कुछ कामों को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए।

वेरिकोज वेंस होने पर बिल्कुल न करें ये काम

- अगर आपको वेरिकोज वेंस की समस्या है, तो ज्यादा देर बिल्कुल खड़े न रहें। इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। ज्यादा देर खड़े रहने के कारण, नसों में खून जमने लगता है इससे नसों पर अधिक प्रेशर पड़ता है।
- वेरिकोज वेंज होने पर, आप भारी वजन न उठाएं। दरअसल, भारी वजन उठाने से नसों पर दबाव पड़ता है और इससे नसों में खिंचाव पैदा होता है। इसकी वजह से नसे कमजोर होने लगती हैं। ऐसा नहीं हैं कि आप बिल्कुल वजन नहीं उठा सकती हैं। लेकिन, अधिक भारी चीजों को उठाने से बचें।
- हाई हील्स वाले सैंडिल न पहनें। इससे ब्लड फ्लो बाधित होता है और नसों पर दबाव पड़ता है।
- वेरिकोज वेंस होने पर, आपको मुलायम और आरामदायक चप्पले पहननी चाहिए।
- अगर आपको वेरिकोज वेंस हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कब्ज न हो। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, आपको कब्ज है, तो इसकी वजह से पेट साफ होने पर नसों पर दवाब आता है और परेशानी बढ़ सकती है।
- अधिक कठोर या खुरदुरी जगह पर न चलें। इससे भी नसों पर प्रेशर आता है।

ट्रेवल के दौरान खराब नहीं होगा डाइजेशन अपनाएं ये टिप्स

क्या ट्रेवलिंग के दौरान आपका भी पेट गड़बड़ हो जाता है,गैसे और कब्ज से परेशान हो जाते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करके इसमें आराम पा सकते हैं।

ट्रेवल करना मजेदार और रोमांच से भरा होता है, लेकिन अक्सर ट्रैवलिंग के दौरा पेट साथ नहीं देता है, अक्सर लोगों को एसिडिटी, कब्ज, जैसी दिक्कत हो जाती है जिसके कारण सफर का मजा किरकिरा हो जाता है, फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम आपको एक्सपर्ट के बताए कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसे फॉलो करने से ट्रेवलिंग के दौर आपको दिक्कत नहीं होगी

- ट्रैवल के दौरान डाइजेशन को सही रखना है तो खाली पेट कैफ़ीन का सेवन करने से बचें, इससे एसिडिटी बढ़ाने की संभावना रहती है।
- रात को सोते वक्त नाभि में तेल जरूर लगाएं, इससे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। पाचन बेहतर होता है और गैस की समस्याएं कम होती है। यह एक बेहद सरल और प्रभावी उपाय है।
- सूर्य नमस्कार करना ना भूलें, इससे न सिर्फ फिटनेस को बढ़ावा मिलता है बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी सक्रिय करने में मदद मिलती है। यह पेट के अंगों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को मजबूत करता है।
- रोज सुबह एक चम्मच शहद का सेवन करें, यह नेचुरल लैक्सेटिव गुणों वाला होता है जो कब्ज और गैस की समस्याओं में मदद करता है।
- ट्रेवल के दौरान ठंडा खाना खाने से बचें, ठंडा खाद्य पदार्थ पाचन को धीमा कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपके भोजन का तापमान सामान्य गर्म हो ताकी पाचन प्रक्रिया सुचारू बनी रहे।
- फलों और दूध को एक साथ ना खाएं, इससे ब्लोटिंग और असुविधा हो सकती है। फल जल्दी पचते हैं जबकि दूध में अधिक समय लगता है।
- सोने से पहले वज्रासन में जरूर बैठें, इससे पेट पर दबाव पड़ता है जो पाचन अंगों को सक्रिय करता है और भोजन को सही से पचने में मदद करता है।
- रात को सोने से पहले कैफीन का सेवन न करें, इससे आपकी नींद खराब हो सकती है और पाचन में बाधा आ सकता है।
- रात का खाना जल्दी खाने से आपके शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इसे पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है और असुविधा की संभावना कम होती है।

उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने लगती है पास की नजर

प्रेसबायोपिया यानी पास की नजर का कमजोर होना है। यह बीमारी उम्र के साथ होने वाले सामान्य बदलाव के कारण होती है जोकि 40 की उम्र के बाद देखने को मिलती है। हालांकि मोबाइल फोन और इसी तरह के अन्य गैजेट्स के इस्तेमाल करने से कई बार यह बीमारी उम्र से पहले ही नजर आने लगती है। इसमें नजर को पास में केंद्रित कर पाने में परेशानी होती है। खासकर छोटे अक्षरों और कम रोशनी में। शुरू में तो व्यक्ति मोबाइल या किताब को दूर कर पढ़ लेता है लेकिन बाद में दिखाई नहीं देता है।

कारण - इसका मुख्य कारण उम्र का अधिक होना है। यह बीमारी 40वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम है, लेकिन मोबाइल, कम्प्यूटर और टेबलेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों को जल्द ही चश्मा लग जाता है। एस्टीमैटिज्म (दृष्टिवैषम्य), नियरसाइटेडनेस (निकटदृष्टि दोष) और फारसाइटेडनेस (दूरदृष्टि दोष) के रूप में प्रेसबायोपिया में अंतर पाया जा सकता है, जो कि आंखों की पुतलियों के आकार से संबंधित है और आनुवांशिक व पर्यावरणीय कारणों से होते हैं।

लक्षण-इलाज - प्रेसबायोपिया के मरीजों को नजदीक का काम करने जैसे कढ़ाई या हाथों से लिखने पर सिरदर्द, आंखों पर दबाव या थकान महसूस होने लगता है। अगर बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में हो जाती है तो दिनचर्या में कुछ बदलाव कर इसको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन बीमारी बढ़ने पर सर्जरी की जाती है। इसके लिए कंडक्टिव कैरेटोप्लास्टी या कॉर्नियल इन-लेज आदि सर्जरी की जाती है।

चश्मा - बायफोकल या प्रोग्रेसिव लैंस लगे चश्मे प्रेसबायोपिया में सुधार के लिए सबसे अच्छे होते हैं। बायफोकल का मतलब है, जिसमें दो फोकस होते हैं। चश्मे के लैंस का प्रमुख भाग दूरदृष्टि दोष के सुधार के लिए होता है जबकि लैंस का निचला हिस्सा निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। प्रोग्रेसिव प्रकार के लैंस बायफोकल लैंस के समान होते हैं लेकिन उनके बीच कोई लकीर नजर नहीं आती। इसको पहन सकते हैं।

जांचें - इसकी जांच भी आंखों की दूसरी बीमारियों की तरह ही होती है। डॉक्टर, पहले आंखों में दवा डालकर पुतलियों को फैलाते हैं। इसके बाद तेज रोशनी में आंखों की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया में करीब एक घंटे का समय लगता है। इसके अलावा भी डॉक्टर कुछ अन्य टैस्ट भी करवाते हैं।

धान खरीदी 2025-26 में एमसीबी आगे, अब तक 4.01 लाख क्विंटल धान का सुरक्षित परिवहन

धान उठाव में एमसीबी जिला बना मिसाल, 45 प्रतिशत से अधिक धान का सुरक्षित परिवहन पूर्ण

एमसीबी। धान खरीदी वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में उपार्जित धान का उठाव कार्य तेज, सुव्यवस्थित और पूरी तरह किसान हितैषी तरीके से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप जिले में धान उठाव की प्रक्रिया निरंतर सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे उपार्जन केंद्रों से धान का सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित हो रहा है।जिले में अब तक कुल 8,79,848.60 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है, जिसमें से 4,00,910.00 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उठाव हो चुका है। यह कुल उपार्जित धान का लगभग 45.57 प्रतिशत है। शेष 4,78,938.60 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में सुरक्षित रूप से संग्रहित है, जिसे उठाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

उपार्जन केंद्रवार उठाव की स्थिति पर नजर डालें तो कछौड़ से 10,940 क्विंटल, केल्हारी से 37,410 क्विंटल, कटकोना से 1,790 क्विंटल, कोड़ा से 16,970 क्विंटल, कौड़ीमार से 35,260 क्विंटल, खड़गवां से 20,930 क्विंटल, बरदर से 29,890 क्विंटल, रतनपुर से 19,650 क्विंटल, सिंगहत से 15,190 क्विंटल, कुंवारपुर से 14,420 क्विंटल, घुटरा से 23,330 क्विंटल, कठौतिया से 22,400 क्विंटल, चैनपुर से 30,860 क्विंटल, नागपुर से 24,040 क्विंटल, बंजी से 17,740 क्विंटल, जनकपुर से 11,410 क्विंटल, बहरासी से 6,240 क्विंटल, डोडकी से 18,960 क्विंटल, माड़ीसरई से 11,620 क्विंटल, सिंगरौली से 900 क्विंटल तथा बरबसपुर से 30,960 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। कई केंद्रों पर उठाव शून्य रहने के बावजूद वहां भी आगामी दिनों में कार्य तेज करने की तैयारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में धान उठाव को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और उनकी मेहनत के सम्मान से जुड़ा दायित्व माना जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रत्येक उपार्जन केंद्र की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि शेष धान का उठाव समय पर, सुरक्षित और बिना किसी असुविधा के पूरा किया जा सके।कुल मिलाकर धान खरीदी वर्ष 2025-26 में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का धान उठाव कार्य एक सशक्त और अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने आया है। सुनियोजित कार्यप्रणाली, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच के चलते यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपार्जित धान का उठाव पूरी पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो।

वाद-विवाद कर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। प्रार्थी पंचुराम साहू उम्र 55 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 02 परपोडी थाना परपोडी, जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 फरवरी 2026 के रात्रि करीबन 01:30 बजे करण साहू निवासी मासुलगोंदी के द्वारा बजरंग बली मंदिर के पास ग्राम तुमडीपार में इसके लडके बलराम साहू से वाद-विवाद कर उसकी हत्या करने की नियत से उसके पेट में धारदार वस्तु से मार कर प्राणघातक हमला कर चोट पहुचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109 ब्हस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी करण साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी मासुलगोंदी को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी करण साहू से पूछताछ में पता चला कि बलराम साहू से आपस में वाद-विवाद होने पर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचना।आरोपी करण साहू पिता दुर्गा साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी मासुलगोंदी, थाना परपोडी जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, डामेश्वर सिंह राजपूत, आरक्षक पीयुष सिंह, शिव कुमार, रमेश चंद्रवंशी, प्रदीप कौशल, प्रमोद पांडेय सहित थाना परपोडी के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

जिला पंचायत सभाकक्ष में श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन आयोजित, 8,704 हितग्राहियों को 2.60 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित

बेमेतरा। जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में बीते बुधवार को श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर शासन की विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं सुझावों को मंच के माध्यम से रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक दिपेश साहू, नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, पार्षद सुश्री नीतू कोठारी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पदमाकर तथा श्रम पदाधिकारी शोएब काजी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि योगेश दत्त मिश्रा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को मजबूती प्रदान करना है। इस अवसर पर विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 8,704 हितग्राहियों को 2,60,82,000/- (दो करोड़ साठ लाख बयासी हजार) रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। योजनानुसार लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण इस प्रकार है– मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 239 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 18 हितग्राही, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 10 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 128 हितग्राही, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 22 हितग्राही, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8,287 हितग्राही, कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए तथा अन्य हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पदमाकर ने बताया कि श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज अद्यतन रखें एवं योजनाओं की जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क बनाए रखें। सम्मेलन का उद्देश्य श्रमिकों को जागरूक करना, योजनाओं की जानकारी देना तथा शासन और श्रमिकों के बीच संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों ने शासन की पहल की सराहना करते हुए इसे लाभकारी बताया। इस प्रकार श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन ने श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त एवं जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

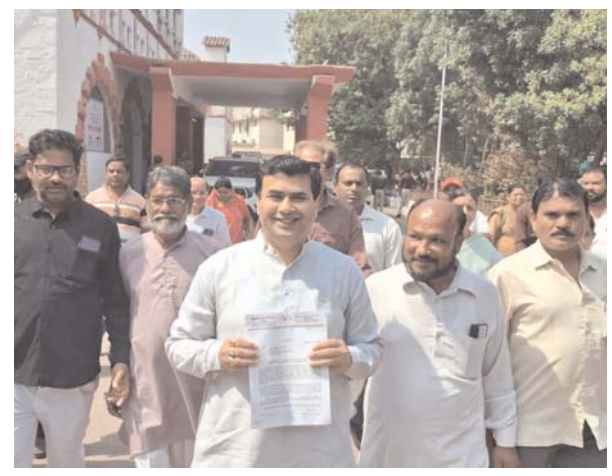

बिना हेलमेट घूम रहे नेताओं पर सवाल उठाना पड़ा भारी, NSUI नेता पर FIR के विरोध में उतरी कांग्रेस

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन करने वाले NSUI दुर्ग शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है।

कलेक्टोरेट का घेराव और ज्ञापन- गुरुवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वरुण केवलतानी पर दर्ज मामले को तत्काल निरस्त करने की मांग की।

राजनीतिक द्वेष का आरोप- शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस निष्पक्षता भूल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि, एक तरफ मंत्री सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी गलती की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले छात्र नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने और राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई है।÷

क्या था पूरा मामला- गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहे थे। इस पर NSUI अध्यक्ष वरुण केवलतानी ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर मंत्री के खिलाफकार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, पुलिस ने इस प्रदर्शन को आधार बनाकर वरुण पर ही मामला दर्ज कर लिया।

आंदोलन की चेतावनी- कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि यह 'झूठी FIR वापस नहीं ली गई, तो पूरी जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के दौरान जिले के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजस्व प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ करें त्वरित कार्रवाई : कलेक्टर श्रीमती प्रजापति

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कलेक्टोरेट के वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में डीएफओ श्री दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भूआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव, आदिवासी विकास, फॉरेस्ट, सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। बैठक में उन्होंने रबी फसलों के डीएससी सर्वे की प्रगति, भू-अर्जन प्रकरणों की स्थिति, वन अधिकार पत्र के मृत हितग्राहियों के नामांतरण, अविवादित एवं विवादित नामांतरण-बंटवारा प्रकरण, सीमांकन कार्य, स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों तथा अभिलेख शुद्धता अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में दस्तावेजी कमी या तकनीकी अड़चनें हैं, उन्हें शीघ्र दूर कर कार्यवाही पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को राजस्व से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

फसल मजबूत करने अब मिलेगा नया खाद, अधिसूचना जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विगत 23 जनवरी को ÷ सल्फर कोटेड यूरिया÷ खाद की अधिसूचना जारी की गई है। यह किसानों के लिए अच्छी खबर है। नई खाद 40 किलो की बोरी में उपलब्ध होगी। इसमें 37 प्रतिशत नाइट्रोजन और 17 प्रतिशत सल्फर होगा। सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण यह खाद पीले रंग की होगी, इसलिए इसका नाम ÷यूरिया गोल्ड÷ भी रखा गया है। फसलों को अच्छी पैदावार और ज्यादा उत्पादन के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है।नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और तनों की बढ़वार में मदद करता है। सल्फर फसल में दाना भरने, तेल और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, मिर्च, लहसुन और प्याज जैसी फसलों के लिए सल्फर बहुत जरूरी माना जाता है। कई सालों से किसान मुख्य रूप से यूरिया और एनपीके खाद का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर की कमी से फसल कमजोर होती है और उत्पादन कम हो सकता है। यूरिया गोल्ड के उपयोग से नाइट्रोजन के साथ-साथ सल्फर भी मिलेगा, जिससे फसल मजबूत और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है।

उड़ीसा के बरगढ़ जिले में राष्ट्रीय दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा आयोजन

जिले के 4 खिलाड़ियों का हुआ चयन

जांजगीर-चांपा । दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहली बार नेशनल दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले के लेंगू मिश्रा क्रिकेट स्टेडियम में (डी.सी.सी.बी.आई) दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 21 से 23 फरवरी तक किया जा रहा है। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जिसमें 04 राज्यों छत्तीसगढ़, उडीसा, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात की टीमों द्वार संयुक्त रूप से भागीदारी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य से जांजगीर-चांपा के चार खिलाड़ियों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया है। इनमें धनंजय यादव (कप्तान), केशव चौहान, राकेश कश्यप तथा अमित बरेठ शामिल हैं। जिले से चयनित खिलाड़ियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे द्वारा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की गई है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम से बढ़ा आत्मविश्वास और मिला तकनीकी मार्गदर्शन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़कर ग्राम कंचरी के कृषक मनोज साहू ने रागी उत्पादन में रचा नया कीर्तिमान

बेमेतरा। बेमेतरा के ग्राम कंचरी के प्रगतिशील कृषक मनोज साहू ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए इस वर्ष एक अभिनव पहल की है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (ऋय्ङ्कङ्घ) के अंतर्गत 0.5 हेक्टेयर भूमि में पहली बार रागी (मंडिया) की खेती कर क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया है। यह प्रयास न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बन रहा है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम से बढ़ा आत्मविश्वास और मिला तकनीकी मार्गदर्शन

श्री साहू ने अपनी रागी फसल का पंजीयन बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य बीज निगम में कराया। इससे उन्हें कृषि विभाग एवं बीज निगम के विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक वैज्ञानिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। बीज उत्पादन के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों, खेत निरीक्षण, पृथक्करण दूरी तथा शुद्धता के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने फसल की विशेष देखभाल की।इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन एवं रोग नियंत्रण के आधुनिक उपायों की जानकारी मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ खेती को अपनाया।

वैज्ञानिक पद्धति से खेती, बेहतर उत्पादन की उम्मीद

मनोज साहू ने पारंपरिक पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके अपनाए, जिनमें शामिल हैं, प्रमाणित एवं अनुशंसित उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग, समय पर बुवाई एवं कतार पद्धति से रोपण, संतुलित एवं मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन, नियमित निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु समुचित एवं समयबद्ध उपाय 7 इन तकनीकों को अपनाने से फसल की वृद्धि अत्यंत संतोषजनक रही है। खेत में फसल की स्थिति हरी-भरी एवं स्वस्थ दिखाई दे रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी उपज प्राप्त होने की प्रबल संभावना है।

पोषण एवं बाजार दोनों दृष्टि से लाभकारी फसल

रागी (मंडिया) एक पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज है, जिसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बदलती खानपान आदतों और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण बाजार में इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में रागी की खेती किसानों के लिए आय का बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। चूंकि श्री साहू की फसल बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत है, इसलिए बीज निगम द्वारा सामान्य बाजार मूल्य की तुलना में अधिक दर मिलने की संभावना है। इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही, भविष्य में वे रागी की खेती का रकबा बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं।

अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण

मनोज साहू की यह पहल दर्शाती है कि यदि किसान शासन की योजनाओं का लाभ लेकर नई एवं वैकल्पिक फसलों को अपनाएं और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, तो वे कम लागत में अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। उनका यह प्रयोग ग्राम कंचरी सहित पूरे जिला बेमेतरा के किसानों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में सामने आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी उनके प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचार से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पोषण सुरक्षा एवं फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रागी उत्पादन एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़कर मनोज साहू ने यह सिद्ध किया है कि नवाचार, वैज्ञानिक सोच और शासकीय योजनाओं का समुचित उपयोग किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उनकी सफलता निश्चित ही जिले में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com